राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

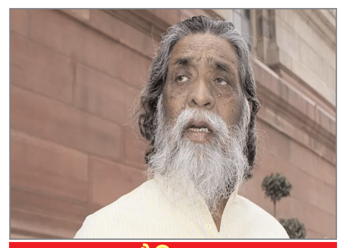

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026
वर्ष 14,अंक 15, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

महमूदाबाद में ट्रैफिक सिस्टम फेल, जाम अतिक्रमण और डायवर्जन से शहर बेहाल..03

भीषण गर्मी में बिजली कटौती से तड़प रहा पंजाब का हर इंसान..04

यूपी में ग्लोबल आस्था का 'महाकुंभ', प्रयागराज ने तोड़ा विदेशी पर्यटकों का रिकॉर्ड, 20 लाख से ज्यादा पहुंचे संगम नगरी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा कानून-व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और धार्मिक पर्यटन को दी गई नई ऊंचाई का असर अब आंकड़ों में दिखने लगा है। साल 2025 यूपी के पर्यटन इतिहास के लिए एक स्वर्णिम अध्याय बनकर उभरा है, जहाँ संगम नगरी प्रयागराज ने विदेशी पर्यटकों की आमद के मामले में एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विजनरी नीतियों और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के चलते आज यूपी की धार्मिक नगरीय दुनिया भर के सैलानियों के लिए आस्था और संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी हैं।

20 लाख विदेशी मेहमान पहुंचे प्रयागराज

पर्यटन विभाग द्वारा जारी वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों में विदेशी पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व उछाल आया है। इनमें सबसे ऊपर प्रयागराज रहा, जहाँ 20,53,918 से अधिक विदेशी श्रद्धालु और पर्यटक संगम की त्रिवेणी में डुबकी लगाने पहुंचे। इसकी तुलना में वाराणसी में 3,21,358, मथुरा में 1,42,134 और राम नगरी अयोध्या में 65,487 विदेशी पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया। यह आँकड़ा साबित करता है कि प्रयागराज अब केवल एक तीर्थस्थल नहीं, बल्कि वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन का सिरमौर बन गया है।

नीतियों और सुरक्षा मॉडल पर बढ़ा वैश्विक विश्वास

विदेशी पर्यटकों की इस भारी संख्या के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' सुरक्षा नीति और मजबूत बुनियादी ढांचा प्रमुख कारण रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर 7-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, अत्याधुनिक एयरपोर्ट और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी ने विदेशी सैलानियों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा किया है। घाटों का सुंदरीकरण, निरंतर साफ-सफाई और आधुनिक प्रकाश व्यवस्था ने प्रयागराज की वैश्विक छवि को और अधिक आकर्षक बनाया है, जिससे यूरोप, अमेरिका और जापान जैसे देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी है।

विश्व रिकॉर्ड के साथ बनी नई पहचान

प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 ने दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम के रूप में नया इतिहास रच दिया है। 13 जनवरी 2025 से शुरू हुए 45 दिवसीय इस आयोजन में कुल 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। विशेष संयोग के कारण इस बार प्रतिदिन औसतन एक करोड़ से अधिक लोगों की मौजूदगी दर्ज की गई, वहीं मात्र 33 दिनों के भीतर 50 करोड़ श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार होना अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। इस महाआयोजन में 300 से अधिक गोताखोरों की तैनाती और 10 लाख लोगों के ठहरने की विशेष व्यवस्था ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूपी की प्रबंधन क्षमता का लोहा मनवाया है।

स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को नई गति

पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रयागराज के उभरने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त लाभ मिला है। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों के आगमन से न केवल पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बल्कि हस्तशिल्प और स्थानीय व्यापार को भी अंतरराष्ट्रीय बाजार मिल रहा है। आने वाले समय में इन आंकड़ों में और अधिक वृद्धि की संभावना है, जो उत्तर प्रदेश को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी।

स्मैक तस्करी का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार

देवरिया। जनपद की सलेमपुर कोतवाली की पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 29.96 ग्राम स्मैक, नकदी और उपकरणों के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक बाल अपचारी भी शामिल है।

पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर वार्ड नंबर 5 हरैया लाला क्षेत्र में छापेमारी की।

इस दौरान कृष्णा गुप्ता (35) और उर्मिला गुप्ता (29) समेत एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से 26 पुड़िया स्मैक (5.72 ग्राम) व 24.24 ग्राम स्मैक, कुल 29.96 ग्राम नशीला पदार्थ, 7.23 लाख रुपये नकद, एक इलेक्ट्रिक तराजू और ओखली-मूसल बरामद किया। इस संबंध में थाना सलेमपुर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में थाना प्रभारी दीपक पटेल समेत पुलिस टीम के अन्य सदस्यों की अहम भूमिका रही।

व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जानकारी स्वीकार नहीं की जा सकती... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा?

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सबरीमाला रेफरेंस सुनवाई के आठवें दिन न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी को स्वीकार नहीं किया जा सकता. यह टिप्पणी वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल के इस निवेदन के जवाब में की गई कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता को स्रोत की परवाह किए बिना स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है. कौल ने एक अखबार में डॉ. शशि थरूर द्वारा लिखे गए लेख का हवाला दिया था, जिसमें धार्मिक राहत के मामलों में न्यायिक संयम बरतने की अपील की गई थी. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि हालांकि न्यायालय सभी प्रख्यात लेखकों और विचारकों का सम्मान करता है, लेकिन यह लेख अंततः एक व्यक्तिगत राय है और व्यक्तिगत राय तो व्यक्तिगत राय ही होती है, यह संकेत देते हुए कि इसका न्यायालय पर कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं हो सकता. कौल ने उत्तर दिया कि सभी स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है. यदि ज्ञान और बुद्धिमत्ता किसी भी स्रोत, किसी भी देश, किसी भी विश्वविद्यालय से आती है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए. हम एक सभ्यता के रूप में इतने समृद्ध हैं कि हम ज्ञान और सूचना के सभी रूपों को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकते।

'किसी धार्मिक संप्रदाय का अधिकार हमेशा सर्वोपरि रहेगा, ये नहीं कहा जा सकता'

इस दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं. मैं इस पर चर्चा नहीं कर रही हूं. मैं इस बात पर ध्यान नहीं दे रही हूं कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है या बुरी, जो इस बहस के लिए वास्तव में अप्रासंगिक है. यह जस्टिस नागरत्ना ने तब कहा, जब कौल ने कहा कि मुद्दा सिर्फ इतना है कि ज्ञान और सूचना जहां से भी आए, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए. कौल दाऊदी बोहरा समुदाय के मुखिया की ओर से बहिष्कार की प्रथा को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका में पेश हो रहे हैं. कौल ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 26(ख) के तहत किसी धार्मिक संप्रदाय के अधिकारों को सभी संदर्भों में अनुच्छेद 25(2)(ख) के अनुसरण में राज्य द्वारा अपनाए गए सामाजिक सुधार कानूनों के अधीन नहीं माना जा सकता. उन्होंने कहा कि देवरू फैसले में यह सामान्य नियम नहीं दिया गया है कि अनुच्छेद 26(घ) सभी संदर्भों में अनुच्छेद 25(2)(ख) के अधीन हो, जैसा कि यह मामला केवल मंदिर प्रवेश के संदर्भ में था. उन्होंने अनुच्छेद 26(ख) और 25(2)(ख) के सामंजस्यपूर्ण अर्थ निकालने की वकालत की. इस बिंदु पर न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि जब अनुच्छेद 25(2)(ख) के तहत कोई कानून बनाया जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि किसी धार्मिक संप्रदाय का अधिकार हमेशा सर्वोपरि रहेगा. वे अधिकार स्वयं सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हैं. यही सामाजिक सुधार या सामाजिक कल्याण कानून का आधार बन सकता है. कौल ने इस बात से सहमति जताई।

संक्षिप्त ख़बरें

बेटे के 'गोल्ड मेडल' की खुशी अधूरी, समारोह में आए पिता की सड़क हादसे में मौत; उज्जैन से आए थे कलबुर्गी

कर्नाटक के कलबुर्गी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मध्य प्रदेश के उज्जैन निवासी शिवकुमार शर्मा अपने बेटे दिव्यांशु को दो स्वर्ण पदक जीतते देखने आए थे, एक दुखद दुर्घटना में अपनी ऑटो पलटने से हादसे का शिकार हो गए. जश्न मनाने के समय, उनके बेटे को अपने पिता को खोने का गहरा सदमा लगा और घर का उत्सवपूर्ण माहौल मातम में डूब गया. विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपने बेटे द्वारा दो स्वर्ण पदक जीतने के ऐतिहासिक क्षण को देखने आए एक पिता की कलबुर्गी में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई. बेटे की उपलब्धि का जश्न मना रहा परिवार अब शोक में डूबा हुआ है. मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के उज्जैन निवासी 59 वर्षीय शिवकुमार शर्मा के रूप में हुई है।

दीक्षांत समारोह के दौरान क्या घटित हुआ?

उज्जैन निवासी शिवकुमार शर्मा के पुत्र दिव्यांशु सक्सेना, कलबुर्गी स्थित केंद्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय (सीयूके) में बी.टेक (ई एंड सी) की पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने दो स्वर्ण पदक जीते हैं. दिव्यांशु को ये स्वर्ण पदक कल (22 अप्रैल) विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में प्राप्त हुए. उनके पिता शिवकुमार अपने बेटे की इस उपलब्धि को देखने के लिए मध्य प्रदेश से कलबुर्गी आए थे. शिवकुमार शर्मा बुधवार सुबह अलंदा तालुक के कडागांची गांव के पास स्थित विश्वविद्यालय परिसर में दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए ऑटो से जा रहे थे. ऑटो चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन पलट गया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई. ऑटो में सवार अन्य लोगों को मामूली चोटें आई. एक तरफ मंच पर उनका बेटा दिव्यांशु पदक पाकर जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ, उसके पिता, जिन्होंने उसे पाला-पोसा था, पास के ही एक अस्पताल में मृत पड़े थे. यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए. इस घटना के संबंध में नारोना पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है।

पत्नी का फिट रहना पति को नहीं था पसंद, जिम से लौटी तो कर दी हत्या, 7 घंटे शव के पास बैठा रहा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

यूपी के मुरादाबाद जिले में एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति के अपनी पत्नी का फिट रहना पसंद नहीं आया और जिम से लौटते की लाहे के राड से वारकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी है. वारदात के अंजाम देने के बाद आरोपी पति करीब 7 घंटे तक शव के पास बैठा रहा. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है. घटना जिले के कटघर थाना क्षेत्र के डबल फाटक इलाके की है. जानकारी के मुताबिक, स्क्रैप कारोबारी शोभित गुप्ता ने अपनी पत्नी पूनम गुप्ता की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वह जिम जाती थी. बताया जाता है कि पूनम के जिम जाने को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था. गुरुवार सुबह जब पूनम जिम से घर लौटी, तो दोनों के बीच फिर से कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर शोभित ने शटर खोलने वाले लोहे के भारी हैंडल से पूनम के सिर पर वार कर दिया. गंभीर चोट लगने से पूनम की मौके

पर ही मौत हो गई।

7 घंटे तक शव के पास बैठा रहा आरोपी पति

घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार होने के बजाए घर में ही मौजूद रहा और करीब सात घंटे तक पत्नी के शव के पास बैठा रहा. इस दौरान दोपहर में उसकी मासूम बेटी स्कूल से घर लौटी और मां के बारे में पूछा, तो आरोपी ने उसे बहलाकर दूसरे कमरे में भेज दिया. शाम होते ही शोभित ने खुद पत्नी के घायल होने की सूचना पुलिस और एंबुलेंस को दी।

ऐसे खुला राज

आरोपी ने पत्नी के घायल होने की सूचना लेकर मामले को हादसा बताने की कोशिश की, जब डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची तो बेड पर महिला का शव पड़ा मिला, जिससे पुलिस को मामला संदिग्ध लगा. पुलिस ने तुरंत शोभित को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

मृतका के परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

मामले में नया मोड़ तब आया जब मृतका के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए. मृतका के भाई ने दावा किया कि यह सिर्फ जिम जाने का विवाद नहीं था, बल्कि उसे लंबे समय से ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था. उसने आरोप लगाया कि पहले भी बहन को मारने की कोशिश की गई थी. उसे कांच का पाउडर खिलाकर मारने की कोशिश की गई थी, जिससे उसकी जीभ और गाल कट गए थे. परिजनों का दावा है कि शोभित के साथ उसके भाई और परिवार के अन्य सदस्य भी इस साजिश में शामिल थे. भाई ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उनकी बहन को इंसाफ मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. वहीं एसपी सिटी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया है।

बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा पश्चिम चंपारण!

बेतिया/नरकटियागंज। जिले में विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से रविवार को बेतिया में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने की। इसमें दिल्ली से आई मंत्री कार्यालय की टीम, जिलाधिकारी तरनजोत सिंह सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और कोल इंडिया के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान जिले के समग्र विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक का प्रमुख विषय जिले में 500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव था। इस परियोजना से ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव होगा। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इसके लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित कर कोल इंडिया को सूचित किया जाएगा। प्रक्रिया को तेज करने के लिए अगले सप्ताह संयुक्त निरीक्षण का कार्यक्रम भी तय किया गया है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए गौनाहा के भितिहरवा में 50 बेड के आयुष अस्पताल की स्थापना पर सकारात्मक सहमति बनी। इससे ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार की होगी।शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण पहल करते हुए एक नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को लेकर चर्चा हुई। जिससे जिले के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। इसके अलावा, मंत्री ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत अन्य विद्यालयों के बुनियादी ढांचे के विकास और अमृत सरोवरों के निर्माण व सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव रखा।

पटना में रसगुल्ला खिलाकर अपने नाम करवा ली जमीन, सीएम सम्राट के दरबार में पहुंचा पीड़ित... मांगा न्याय

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिहार में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग ने आरोप लगाया है कि उन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर उनकी जमीन हड़प ली गई. यह मामला तब सुर्खियों में आया जब मधेपुरा जिले के मुरलीगंज निवासी 76 वर्षीय जगदीश मुखिया ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के जनता दरबार में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई. जगदीश मुखिया ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कुछ भू-माफियाओं ने उन्हें पेंशन बढ़ाने का झांसा देकर जिला मुख्यालय ले गए और वहां धोखे से जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली. पीड़ित के अनुसार, इस मामले में मुरलीगंज थाना में नामजद प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने बताया कि वह पहले भी सीओ, डीसीएलआर, एसपी और डीएम सहित कई अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी।

रसगुल्ले में मिलाकर खिलाया नशीला पदार्थ

पीड़ित की बहू पूजा कुमारी ने आरोप लगाया कि उनके ससुर को रसगुल्ले में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाया गया, जिसके बाद उनसे जमीन के कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिए गए. उनका कहना है कि बार-बार प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्हें मजबूर होकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

सीएम ने दिए जांच के आदेश

मुख्यमंत्री द्वारा इस पूरे मामले में तुरंत जांच के आदेश दिए जाने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है. स्थानीय स्तर पर भी इस घटना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. वहीं पीड़ित का कहना है कि अब उन्हें केवल मुख्यमंत्री से ही न्याय मिलने की उम्मीद है. वहीं स्थानीय अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच की जा रही है. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अप्रैल में ही सूखने लगीं पहाड़ी नदियां, पानी की कमी से जूझते किसान, सिंचाई की तत्काल जरूरत

नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण) । गर्मी शुरू होते ही कई छोटी छोटी पहाड़ी नदियां सुख गई हैं। पंडई और हड़बोड़ा नदियां सूखने के कगार पर पहुंच गई है। बीते साल कम वर्षा और बढ़ रही गर्मी से ऐसी स्थिति बन रही है। अप्रैल के आरंभ में हीं नदी का प्रवाह करीब करीब थम गया है। दर्जनाधिक गांवों के करीब 500 से अधिक किसान नदी से गन्ने की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने वाली पंडई में जहां- तहां पानी दिख रहा है, जो नदी की पेटी में नाले का आकार ले ली है। उससे सिंचाई करना मुश्किल है। यह नदी नेपाल से निकलकर भारतीय सीमा के भिखनाठोरी और जंगल होते हुए मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है। सीमा से गौनाहा और नरकटियागंज क्षेत्र में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर सिकरहना नदी में मिलती है। लेकिन नदी की हालत देख तटीय गांव के लोग मई और जून की तपिश में नदी के हालात को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि तटीय गांवों के किसान पंपसेट लगाकर नदी से फसलों की सिंचाई कर ले रहे थे, जो अब मुश्किल हो गई है। कहीं एक फिट तो कहीं डेढ़ फीट पानी रह गया है।गौनाहा के आदर्श श्रीवास्तव, रुपवलिया के प्रमोद कुमार का कहना है कि पंडई नदी का जलस्तर पेटी में चला गया है। इससे सिंचाई नहीं हो सकती। अभी गर्मी की शुरुआत है।

शनि दोष हटा देंगे...' ठगों के जाल में फंसा बुजुर्ग, गहने हो गए गायब

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महाराष्ट्र के जलगांव में ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां अंधविश्वास का सहारा लेकर दो बदमाशों ने एक बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया और दो ग्राम सोने की अंगूठी और 900 रुपये लेकर फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस ठगों की तलाश कर रही है।

जानकारी के अनुसार 67 वर्षीय गजानन विठोबा सरजेराव किसी काम से बस स्टैंड गए थे. इसी दौरान दो लोगों ने उन्हें बातों में उलझाया और खुद को जानकार बताते हुए कहा कि उन पर शनि ग्रह का असर है, जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है. ठगों ने डर का माहौल बनाते हुए उन्हें झांसे में लिया और दावा किया कि वह उनका शनि दोष दूर कर सकते हैं।

पहले दिलाया भरोसा, फिर की ठगी

ठगों ने पहले चालाकी से बुजुर्ग का भरोसा जीता. बदमाशों ने एक छोटा पत्थर लेकर कुछ मंत्र बोलने को कहा और फिर उसे रुद्राक्ष में बदलने का दिखावा किया. इस कथित चमत्कार से बुजुर्ग उनके झांसे में आ गया. इसके बाद दोनों उन्हें बस स्टैंड के पास एक बंद पड़ी पुलिस चौकी के पास ले गए, जहां उन्होंने और उपाय करने की बात कही. ठगों ने बुजुर्ग से सोने की अंगूठी और जेब में रखे पैसे निकालकर अपने हाथ में रखने को कहा और उन्हें आगे देखने के लिए कहा, जैसे ही बुजुर्ग आगे बढ़ा, दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो ठगी का एहसास हुआ।

सोने की अंगूठी और पैसे लेकर ठग फरार

ठगो ने करीब दो ग्राम सोने की अंगूठी और 900 रुपये लेकर फरार हो गए. घटना 20 अप्रैल को नवीन बस स्टैंड इलाके में हुई. पीड़ित की शिकायत के आधार पर जिला पेठ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया और ठगो की तलाश कर रही है. पुलिस का कहना है कि इस तरह के गिरोह इन दिनों सक्रिय हैं, जो धार्मिक आस्था, अंधविश्वास और चमत्कार के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं. खासकर बुजुर्ग और श्रद्धालु आसानी से इसके झांसे में आ जाते हैं और ठगी का शिकार बन जाते हैं।

'मेरी मां के साथ...', कानपुर कोर्ट की बिल्डिंग से वकील ने लगाई छलांग, सुसाइड नोट में लिखी कहानी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कानपुर कचहरी परिसर में गुरुवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब एक वकील ने कचहरी परिसर की 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी. घटना के बाद कचहरी में अफरा-तफरी मच गई. सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता मौके पर इकट्ठा हो गए. आनन-फानन में घायल वकील को उर्सला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान प्रियांशु श्रीवास्तव के रूप में हुई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोपहर के समय प्रियांशु अचानक 5वीं मंजिल की रेलिंग के पास पहुंचा और नीचे कूद गया. शोर-शराबा सुनकर आसपास के चैम्बर्स से वकील और वादी बाहर निकल आए. सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और विधिक कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने प्रियांशु का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

PCS परीक्षा पास नहीं कर सका था

शुरुआती जांच में एक चौंकाने वाला

खुलासा हुआ. प्रियांशु ने आत्मघाती कदम उठाने से ठीक पहले अपने वॉट्सऐप स्टेटस पर दो पन्नों का सुसाइड नोट पोस्ट किया था. इस नोट में उसने अपने जीवन के संघर्षों और मानसिक पीड़ा का जिक्र किया. सुसाइड नोट में प्रियांशु ने लिखा कि, 'उसने 2016 में LLB की पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद वह PCS परीक्षा पास नहीं कर सका. घर की आर्थिक स्थिति और पिता के खराब स्वास्थ्य के कारण वह लंबे समय से तनाव में था।

मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं

प्रियांशु ने आगे लिखा कि, 'परिवार की जिम्मेदारियों के चलते लगातार संघर्ष करता रहा. घर के खराब हालात के कारण वह मानसिक रूप से परेशान था, लेकिन उसने कभी किसी से अपनी परेशानी जाहिर नहीं की.' ?भावुक कर देने वाले इस नोट में प्रियांशु ने स्पष्ट किया कि उसकी मौत के लिए कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है. उसने अपनी मां की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए लिखा, 'मेरे जाने के बाद मेरी मां को कोई परेशान न करे. मेरी वजह से मां को कोई तकलीफ न देना।

इस पूरे मामले में पुलिस के अनुसार, मोबाइल स्टेटस और सुसाइड नोट के हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है. शुरुआती तौर पर यह मामला अवसाद (डिप्रेशन) और पारिवारिक संघर्ष का लग रहा है. पुलिस परिजनों से भी पूछताछ कर रही है, ताकि घटना के पीछे के अन्य संभावित कारणों का पता लगाया जा सके।

पुस्तकें: भीतर की दुनिया को समझने और बदलने का माध्यम

पुस्तकें: जो अकेलेपन को भी अपना बना लेती हैं
शब्दों से परे एक दुनिया: जहाँ विचार जीवंत हो उठते हैं

ज्ञान की सबसे प्रखर रोशनी दीपक से नहीं, खुले पन्नों से निकलती है। विचारों के शोर में भटकता मन जब ठहराव चाहता है, तब पुस्तक भीतर नई दुनिया का द्वार खोल देती है। 23 अप्रैल इसी अद्भुत संसार को समर्पित दिन है, जब पुस्तकें केवल वस्तु नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली शक्ति के रूप में सम्मानित होती हैं। यह स्मरण कराता है कि शब्द केवल भाषा नहीं, बल्कि सभ्यता की धड़कन और युगों का अनुभव हैं। हर पुस्तक अनुभव, संघर्ष और कल्पना का दस्तावेज है, जो समय से परे जाकर पीढ़ियों से संवाद करती रहती है। इसी कारण यूनेस्को ने 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस घोषित किया, क्योंकि इसी दिन शेक्सपियर और सर्वेंटेस का निधन हुआ था।

पठन केवल आँखों से किया जाने वाला क्रिया नहीं, बल्कि मन और मस्तिष्क की गहराइयों में उतरती एक निरंतर यात्रा है। जैसे-जैसे कोई व्यक्ति पन्नों को पलटता है, वैसे-वैसे वह अपने भीतर भी नई परतों को खोजता चलता है। साहित्य, विज्ञान, इतिहास या दर्शन–प्रत्येक विधा अपने भीतर एक संपूर्ण ब्रह्मांड समेटे होती है। पुस्तकें हमें उन स्थानों तक पहुँचा देती हैं जहाँ हमारा भौतिक अनुभव सीमित होता है, और उन विचारों से परिचित कराती हैं जिनकी कल्पना तक पहले संभव नहीं होती। इसी कारण पठन केवल ज्ञान का विस्तार नहीं करता, बल्कि सोचने की क्षमता को व्यापक बनाता है और दृष्टिकोण को गहराई एवं परिपक्वता प्रदान करता है।

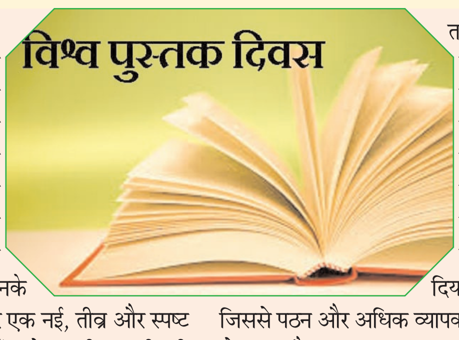

पुस्तकें अकेलेपन को भी भीतर से भर देती हैं और मौन को भी एक जीवंत संवाद में बदल देती हैं। जब बाहरी दुनिया थम जाती है, तब उनके शब्द मन के भीतर एक नई, तीव्र और स्पष्ट आवाज़ रचते हैं। वे कभी हमारी ही अनुभूतियों को पहचान देती हैं और कभी उन अनकहे प्रश्नों के उत्तर बन जाती हैं, जिन्हें हम स्वयं भी ठीक से नहीं कह पाते। किसी कथा का पात्र अचानक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, तो कोई विचार जीवन की दिशा ही मोड़ देता है। इसी कारण पढ़ना केवल आदत नहीं रह जाता, वह भीतर उतरने और स्वयं को नए रूप में देखने की यात्रा बन जाता है। पुस्तकों के साथ बीता हर क्षण आत्म-खोज का अवसर होता है। मुंशी प्रेमचंद की 'गोदान' में ग्रामीण भारत के किसान होरी के संघर्ष का ऐसा सजीव चित्रण मिलता है कि वह केवल कहानी नहीं रह जाती, बल्कि सामाजिक यथार्थ और अन्याय के प्रति पाठक के भीतर गहरी संवेदना जगा देती है।

आज का युग पठन को एक नए विस्तार तक ले गया है। ज्ञान अब केवल पुस्तकालयों की सीमाओं में बंद नहीं रहा, बल्कि डिजिटल माध्यमों ने उसे हर व्यक्ति की पहुँच तक पहुँचा दिया है। मोबाइल स्क्रीन, ई-पुस्तकें और श्रव्य पुस्तकें ज्ञान के सहज और आधुनिक स्रोत बन गई हैं। इस बदलाव ने पढ़ने को अधिक सरल, लचीला और समय के अनुकूल बना दिया है। अब व्यक्ति यात्रा में, विश्राम के क्षणों में या रात्रि की शांति में भी अध्ययन कर सकता है। तकनीक ने पुस्तकों को समाप्त नहीं किया, बल्कि उन्हें नए रूपों में फिर से जीवंत कर दिया है, जिससे पठन और अधिक व्यापक व प्रभावी हो गया है।पठन का प्रभाव व्यक्ति की सीमाओं से आगे बढ़कर पूरे समाज की चेतना को आकार देता है। जैसे-जैसे लोग पढ़ते हैं, वैसे-वैसे उनकी समझ गहरी होती जाती है और वे अधिक संवेदनशील, विवेकशील तथा विचारशील बनते हैं। पुस्तकों के माध्यम से विविध संस्कृतियों, विचारधाराओं और जीवनशैलियों को समझने का अवसर मिलता है, जिससे समाज में सहिष्णुता और स्वीकार्यता की भावना मजबूत होती है। एक पढ़ा-लिखा समाज जल्दबाज़ी में निर्णय नहीं लेता, बल्कि तर्क, अनुभव और समझ के आधार पर आगे बढ़ता है। इस प्रकार पुस्तकें केवल ज्ञान का विस्तार नहीं करतीं, बल्कि एक संतुलित, जागरूक और प्रगतिशील समाज की आधारशिला भी रखती हैं।

शब्दों की शक्ति जब विचारों का रूप लेकर समाज की दिशा बदलने लगती है, तब रचनाकारों का योगदान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह दिवस उन सृजनशील लेखकों के सम्मान का अवसर है, जो अपने अनुभव, कल्पना और संवेदना को शब्दों में ढालकर नई दृष्टि प्रदान करते हैं। कॉपीराइट जैसी व्यवस्थाएँ उनकी रचनात्मकता की रक्षा करती हैं और उन्हें उनके कार्य का उचित एवं न्यायसंगत सम्मान सुनिश्चित करती हैं। डिजिटल युग में, जहाँ सामग्री का प्रसार अत्यंत तीव्र गति से होता है, वहाँ ऐसी सुरक्षा और भी आवश्यक हो जाती है। यह केवल एक कानूनी व्यवस्था नहीं, बल्कि रचनात्मकता के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी और सम्मान का प्रतीक है।

पुस्तकें जीवन के हर चरण में समान रूप से साथ निभाने वाली सच्ची मार्गदर्शक होती हैं। बाल्यावस्था में वे कल्पना को पंख देती हैं, युवावस्था में लक्ष्य और दिशा प्रदान करती हैं, और वृद्धावस्था में स्मृतियों एवं अनुभवों को फिर से जीवंत कर देती हैं। गाँव हो या शहर, समृद्ध परिवेश हो या साधारण जीवन–पुस्तकों की पहुँच सभी के लिए समान अवसर का द्वार खोलती है। वे यह बोध कराती हैं कि जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि उसे समझने, जानने और निरंतर सीखते रहने की यात्रा है। पठन मनुष्य को भीतर से सशक्त बनाता है और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, आत्मबल तथा आशा बनाए रखने की क्षमता प्रदान करता है।

पुस्तकों का महत्व किसी सीमा में नहीं बाँधा जा सकता, क्योंकि वे समय से परे जाकर मनुष्य के भीतर ज्ञान और चेतना का निरंतर विस्तार करती रहती हैं। हर पृष्ठ एक नई दृष्टि और नया विचार देता है, जो जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतुलित बनाता है। पठन व्यक्ति को केवल सूचनाएँ नहीं देता, बल्कि उसे भीतर से अधिक जागरूक, विचारशील और संवेदनशील बनाता है। 23 अप्रैल का यह दिन हमें स्मरण कराता है कि पुस्तकें जीवन की सच्ची मार्गदर्शक हैं, जो हमारी सोच को विस्तार देती हैं और अस्तित्व को समृद्ध करती हैं। इसलिए पठन को केवल एक आदत नहीं, बल्कि जीवन का अनिवार्य और सतत हिस्सा बनाना चाहिए।

कृति आरके जैन

इलाज का बोझ

किसी लोक कल्याणकारी सरकार का पहला दायित्व बनता है कि वो अपने नागरिकों के लिए सस्ती व प्रभावी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये। दुनिया के तमाम देशों में सरकारों के स्तर पर ऐसी नीतियां बनी हैं कि लोगों को स्वास्थ्य संकट आने पर उपचार खर्च के तनाव का रोग अलग से नहीं लेना पड़ता है। विशेषकर बुजुर्ग आबादी का विशेष ख्याल रखा जाता है। जिस उम्र में उनका शरीर क्षीण हो रहा होता है और आय के साधन न के बराबर होते हैं, सरकारी चिकित्सा का सुरक्षा कवच बड़ा संबल होता है। विडंबना यह है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं गहरे विरोधाभास से जूझ रही हैं। हमारी सरकारी चिकित्सा व्यवस्था खुद बीमार है। देश में कम स्वास्थ्य बजट, राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार के चलते सरकारी अस्पतालों में सब कुछ होते हुए भी गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों को गुणवत्ता का उपचार नहीं मिल पाता है। हाल ही में सामने आए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक नये सर्वेक्षण में बताया गया है कि देश की लगभग आधी आबादी के पास किसी न किसी प्रकार का स्वास्थ्य बीमा कवर है। लेकिन विडंबना यह है कि स्वास्थ्य बीमा कवर होने के बावजूद उनकी जेब से खर्च होने वाला चिकित्सा व्यय अधिक बना हुआ है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार द्वारा समर्थित योजनाओं ने बीमा कवरेज के विस्तार को गति दी है। उल्लेखनीय है कि देश के ग्रामीण इलाकों में अब शहरी क्षेत्रों के मुकाबले बीमा कवरेज अधिक है। इसके बावजूद दुखद स्थिति यह है कि देश के करोड़ों परिवारों के लिए आज भी बीमार पड़ना गंभीर आर्थिक संकट पैदा कर देता है। वहीं दूसरी ओर, इस सर्वेक्षण ने एक स्पष्ट खामी को भी उजागर किया है कि आज भी अस्पताल में भर्ती होने के प्रत्येक मामले के लिए मरीज के जेब से होने वाले खर्च के औसत बिल 34,000 रुपये से अधिक हैं। यह हकीकत है कि बीमा कवरेज के बाद भी मरीजों के उपचार पर होने वाला खर्च भारत के अधिकांश आम परिवारों की वहन क्षमता से कहीं अधिक है।

आखिर देश में बीमा दायरा बढ़ने के बावजूद, मरीजों पर चिकित्सा उपचार का आर्थिक बोझ लगातार क्यों बढ़ रहा है? क्या बीमा कवरेज कारोबार के लिए उत्साहित रहने वाली बीमा कंपनियों और बड़े अस्पतालों की कमाई का ही जरिया बनकर रह गया? हाल के वर्षों में इस अपवित्र गठबंधन के कई मामलों का खुलासा भी हुआ है। लेकिन नियामक तंत्र की सख्ती के अभाव में मरीजों के दोहन का यह खेल बदस्तूर जारी है। जानकार बताते हैं कि चिकित्सा उपचार की बढ़ती दर अक्सर मुद्रास्फीति से भी अधिक होती है। निस्संदेह, यह अपवित्र कारोबार मरीजों से मुनाफा कमाने वालों के मानवीय सरोकारों पर सवालिया निशान लगाता है। वैसे चिकित्सा सेवा में मुनाफा बढ़ते देख निजी स्वास्थ्य सेवाओं का दबदबा भी बढ़ा है। हाल के वर्षों में सरकारी अस्पतालों की बदहाली के चलते ज्यादातर भारतीय निजी अस्पतालों की ओर ही रुख कर रहे हैं। लेकिन वहां सरकारी अस्पतालों से कई गुना अधिक उपचार लागत होती है। कोरोना संकट में हमने देखा कि महंगे उपचार के चलते तमाम लोग गरीबी के दलदल में चले गए। दरअसल, आज हालातवश सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं वाले अस्पतालों में भर्ती होने की हिस्सेदारी घटने के साथ ही मरीजों को अनिवार्य रूप से अधिक महंगे विकल्पों की ओर धकेला जा रहा है, जिससे बीमा सुरक्षा के लाभ कम हो रहे हैं। आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख योजनाओं का त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन भी एक और बाधा बनी है। वहीं देर से मिलने वाली सरकारी चिकित्सा बीमा राशि भी मरीजों के लिए किफायती सेवाओं को बाधित कर रही है। यदि इन सरकारी योजनाओं में सूचीबद्ध अस्पताल मरीजों के उपचार से पीछे हट जाते हैं तो सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित बीमा की अवधारणा खतरे में पड़ जाती है, जिससे वंचित होने से नागरिकों का उपचार अधर में लटक जाएगा। निस्संदेह, बीमा कवरेज ही काफी नहीं है, देश को अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को भी मजबूत करना होगा। साथ ही सरकारी योजनाओं के तहत समय पर भुगतान सुनिश्चित करना होगा। अन्यथा अस्पताल के बिल मजबूर लोगों की आय व बचत को पलीता लगाते रहेंगे।

संपादकीय

अधिकारों की तुलना में कर्तव्य और जिम्मेदारियां के प्रति हम ज्यादा अनभिग्य

(विमर्श) स्त्रियां कर्तव्यों के प्रति अधिक संवेदनशील।

महात्मा गांधी ने कहा था कि 'अधिकारों का वास्तविक स्रोत कर्तव्य है, यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो अधिकार अपने आप मिल जाएंगे, '

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में अधिकार और कर्तव्य के बीच संतुलन का प्रश्न केवल संवैधानिक बहस का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का आईना भी है। इसी प्रकार भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण के समय यह स्पष्ट किया था कि 'संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, तो वह असफल हो जाएगा,' यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है क्योंकि कानून और नियम केवल कागज़ पर नहीं, बल्कि नागरिकों की चेतना और कार्यों में जीवित रहते हैं। आज हम जिस दौर में खड़े हैं, वहाँ एक ओर जनसंख्या का विस्तार, स्त्री-पुरुष अनुपात की जटिलता और शिक्षा का असमान वितरण दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर अधिकारों के प्रति तीव्र आग्रह और जिम्मेदारियों के प्रति अपेक्षाकृत शिथिल उदासीनता भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। यह विडंबना ही है कि जिस देश ने विश्व को वसुधैव कुटुम्बकम् और कर्तव्य ही धर्म है जैसे विचार दिए, उसी समाज में आज अधिकारों की माँग तो प्रमुखता से अंगीकार और स्वीकार करने की चाहत रखता है, परंतु कर्तव्यों और जिम्मेदारियां के निर्वहन में परिपक्वता का अभाव एवं दुराग्रह दिखाई देता है। भारत की जनसंख्या, जो अब विश्व में शीर्षतम जनसंख्या वाले देशों में शामिल है, यहां केवल संख्या का विषय नहीं बल्कि गुणवत्ता का प्रश्न भी है यह गुणवत्ता शिक्षा, सामाजिक समझ और संवैधानिक चेतना, जागरूकता पर आधारित होती है। जब हम स्त्री-पुरुष अनुपात की बात करते हैं, तो यह केवल आंकड़ों का संतुलन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और अवसरों की समानता का संकेतक है। किंतु जब तक दोनों ही वर्ग अपने अधिकारों के साथ- साथ अपने कर्तव्यों को समान रूप से नहीं समझेंगे, तब तक वास्तविक प्रगति अधूरी और दिवा- स्वप्न ही रहेगी। शिक्षा इस पूरे विमर्श का केंद्र बिंदु है, क्योंकि शिक्षित समाज ही अधिकार और जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है, परंतु भारत में शिक्षा का प्रसार अभी भी समरूप नहीं है।ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच, स्त्री और पुरुष के बीच, तथा विभिन्न आर्थिक वर्गों के बीच एक गहरी और बड़ी खाई मौजूद है। परिणामस्वरूप, एक बड़ा वर्ग अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक हो रहा है, परंतु कर्तव्यों के प्रति उसकी समझ अभी भी सीमित संकुचित है। भारतीय संविधान, जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, उसी के साथ मौलिक कर्तव्यों की भी स्पष्ट व्याख्या करता है, किंतु व्यवहारिक जीवन में अधिकारों की चर्चा अधिक होती है और कर्तव्यों की उपेक्षा। महात्मा गांधी ने कहा था कि 'अधिकारों का वास्तविक स्रोत कर्तव्य है, यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो अधिकार अपने आप मिल जाएंगे,' परंतु आधुनिक समाज में यह विचार धीरे-धीरे पृष्ठभूमि में चला गया है।

इसी प्रकार डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण के समय यह स्पष्ट किया था कि 'संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, तो वह असफल हो जाएगा,' यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है क्योंकि कानून और नियम केवल कागज़ पर नहीं, बल्कि नागरिकों की चेतना में जीवित रहते हैं। भारत में कानूनों की कमी नहीं है सड़क सुरक्षा से लेकर महिला संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण से लेकर शिक्षा के अधिकार तक हर क्षेत्र में स्पष्ट नियम बनाए गए हैं, लेकिन उनका पालन तभी संभव है जब नागरिक स्वयं जिम्मेदारी का परिचय दें। उदाहरण के लिए, सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि सामाजिक अनुशासन की कमी का संकेत है।इसी प्रकार, महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून तब तक प्रभावी नहीं हो सकते जब तक समाज में लैंगिक संवेदनशीलता और सम्मान की भावना विकसित न हो। स्त्री-पुरुष समानता के संदर्भ में भी यह स्पष्ट है कि अधिकारों की माँग के साथ-साथ कर्तव्यों का निर्वहन भी उतना ही आवश्यक है।जहाँ महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं, वहीं समाज के सभी वर्गों को उनके प्रति सम्मान और सहयोग का कर्तव्य निभाना होगा। शिक्षा का स्तर बढ़ने के बावजूद यदि नैतिक शिक्षा और नागरिकता के मूल्यों का समावेश नहीं होगा, तो केवल डिग्रीधारी नागरिक तैयार होंगे, जागरूक और जिम्मेदार कर्तव्य निस्ट नागरिक नहीं। आज सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने अधिकारों की आवाज़ को मजबूत किया है, लेकिन कई बार यह जागरूकता एकतरफा हो जाती है, जहाँ केवल अधिकारों की बात होती है और जिम्मेदारियों की चर्चा गौण हो जाती है।

यही असंतुलन समाज में तनाव और गहरे हरेअसंतोष को जन्म देता है। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा प्रणाली में प्रारंभ से ही नागरिक कर्तव्यों पर बल दिया जाए, परिवार और समाज में जिम्मेदारी की भावना को विकसित किया जाए, और शासन स्तर पर भी जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को यह समझाया जाए कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक आम नागरिक स्वयं कानूनों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक कोई भी व्यवस्था पूरी तरह सफल नहीं हो सकती। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में नागरिक ही सर्वोच्च शक्ति हैं, और उनकी परिपक्वता ही राष्ट्र की दिशा और दशा तय करती है। इसलिए यह सही समय आत्ममंथन का है क्या हम केवल अपने अधिकारों के लिए सजग हैं, या अपने कर्तव्यों के प्रति भी उतने ही प्रतिबद्ध हैं? यदि इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण ईमानदारी और सजगता से खोजा जाए, तो स्पष्ट होगा कि हमें अभी लंबा सफर तय करना है। जागरूकता, शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के समन्वय से ही वह दिन आएगा जब भारत केवल अधिकारों के प्रति नहीं, बल्कि कर्तव्यों के प्रति भी समान रूप से परिपक्व राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा जिससे विकास की गति को सदैव सशक्त बल मिलेगा और विकास की संभावना चारों दिशाओं में व्याप्त होगी।

कविता

संजीव-नी।

फिर से मासूम नन्हे हो जाएँ।
जैसे पहली बार ओस को
हथेली पर रखा ,
वह मुस्कुरा उठी
फिर उतने ही छोटे हो जाएँ
आकाश हमें अनंत लगे,
उसकी नीली चुप्पी में
सपनों की पतंग लहरा दें।

जहाँ कोई छल न हो,
बस मिट्टी में उगती
सोंधी-सी सच्चाई हो,
आँखें पानी सी निर्मल हों
हृदय शिवालय की घंटी-सा
शिव शिव बोल उठे।

फिर से वैसे ही हो जाएँ
पहली बार 'राम' नाम सुना
किसी लोरी की तरह नहीं,
शीतल कोमल हवा की तरह
भीतर गुंजा।

ईश्वर किताबों में नहीं,
पेड़ों की छाँव में निहारता
जहां माँ की उँगलियों में
पूजा अर्चना का
सात्विक मायने छिपा।

फिर से मासूम नन्हे हो जाएं
जीतने की जल्दी न हो,
गिरकर भी
खिलखिलाने का हौसला हो,
जहाँ किसी के आँसू देखकर
द्रवित सी निर्झरणी बहने लगे।

इतने छोटे हो जाएँ
कि दुनिया की सारी ईर्ष्या
ओठों तक पहुँच ही न पाए,
हम अपनी जेब में
शीतल छांव के बादल
रखकर सबको भीतर
समेट लें।
फिर से मासूम नन्हे हो जाएँ
एक शुभ प्रार्थना बन जाए
और हम
प्रार्थना के सबसे भोले शब्द।

संजीव ठाकुर

परिसीमन बिल गिरने से देश को तो लाभ हुआ

देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को 33 फीसदी राजनीतिक आरक्षण देने वाला ऐतिहासिक बिल लोकसभा में भले ही गिर गया हो किंतु भाजपा को जो लाभ मिलना था, वह मिल या। इस बिल के माध्यम से वह यह संदेश देने में कामयाब रही कि हम तो महिलाओं को संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण देना चाहते है, कितु विपक्ष नही चाहता। विपक्ष भी इस बिल के गिरने को अपनी विजय मानता है। इस बिल के गिरने से भाजपा को लाभ मिले या विपक्ष को किंतु सबसे बड़ा लाभ देश को हुआ है। इस बिल के पास होने से बढ़ने वाली लोकसभा और विधान सभा सीट के सांसदों के वेतन और भत्तों का खर्च बच गया। नए सांसदों और विधायकों की पेंशन की राशि का बोझ अब देश को नही उठाना पड़ेगा।

मोदी सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में वर्तमान सीटों की संख्या एकमुश्त बढ़ाकर डेढ़ गुना करने का जो प्रस्ताव इस बिल में किया था, उसका लाभ कुल मिलाकर 2250 सीटों का होता। लोकसभा में वर्तमान 545 सीटों के हिसाब से की महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से 205 सीटें बढ़तीं, जबकि सभी 28 राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में 2045 सीटों का इजाफा होता। यानी 70 करोड़ महिलाओं में से मात्र 2250 महिलाएं चुनकर विधानमंडलों में पहुंचतीं। इसमें राज्यसभा और विधानपरिषदों की सीटें शामिल नहीं हैं, क्योंकि उनकी संख्या बाद में तय होगी। तर्क दिया जा सकता है कि इस आरक्षण को महिलाओं की संख्या की बजाए उनके राजनीतिक-सामाजिक सशक्तिकरण, लैंगिक समता और राजनीतिक नैतिकता की पवित्र मंशा के आईने में देखा जाना चाहिए। सही है। लेकिन अगर बिल पास हो जाता। सासंदों और विधायकों के क्षेत्र और सीट बढ़ जाती तो वढ़े सासदों , विधायकों के वेतन, भत्ते, सुविधाओं और पेंशन का बोझ तो देश पर ही पड़ता।

12 साल के कार्यकाल में यह पहला अवसर था, जब मोदी सरकार की संसद में विधायी हार हुई। संसदीय इतिहास में 1990 में पंचायत सशक्तिकरण संशोधन बिल के राज्यसभा में गिरने के बाद यह पहला बिल है, जो लोकसभा में ही ढ़ह गया। वैसे मोदी सरकार चाहती तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण बिल अपने दूसरे कार्यकाल में ला सकती थी, जब एनडीए के अपने 353 सांसद थे और कोई भी संशाधन बिल आसानी से पारित हो सकता था। लेकिन उसने तब ऐसा नहीं किया। भारतीय राजव्यवस्था में पिछले कुछ वर्षों से वित्तीय प्रबंधन और संसाधनों के आवंटन को लेकर एक व्यापक बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के नाम पर पुरानी पेंशन योजनाओं और सैन्य भर्ती की पारंपरिक प्रक्रियाओं में आमूलचूल परिवर्तन कर रही है, वहीं दूसरी ओर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के विस्तार के नाम पर विधायी निकायों के आकार को बढ़ाने की योजनाएं भी चर्चा के केंद्र में हैं। इन निर्णयों का भारतीय अर्थव्यवस्था और आम नागरिक के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सरकार के इन कदमों के पीछे तर्क दिया जाता है कि आधुनिक समय की चुनौतियों से निपटने के लिए संसाधनों का कुशल उपयोग अनिवार्य है, लेकिन जब बात सांसदों और जनप्रतिनिधियों की सुविधाओं की आती है, तो जनता के बीच विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

पेंशन के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों में व्यापक असंतोष देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने वित्तीय बोझ को कम करने के लिए लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के स्थान पर नई पेंशन योजना (एनपीएस) को प्राथमिकता दी है। हालिया वर्षों में महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि तो की गई है, जैसे कि 2026 के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार इसे 60 प्रतिशत तक पहुँचाया गया फिर भी यह वृद्धि कर्मचारियों की उन मांगों को शांत करने में विफल रही है। वे तो सेवानिवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित आय की गारंटी चाहते हैं।

सरकार का तर्क है कि पेंशन पर होने वाला खर्च भविष्य में विकास कार्यों के लिए उपलब्ध बजट को कम कर सकता है, इसलिए निवेश-आधारित पेंशन प्रणाली अधिक व्यावहारिक है। हालांकि, सरकारी कर्मचारी इसे अपनी सामाजिक सुरक्षा में कटौती के रूप में देखते हैं, जिससे उनके भविष्य की स्थिरता पर सवालिया निशान लग जाते हैं। अर्थशास्त्री दावा करते हैं कि यदि पुरानी पेंशन दी गई तो कुछ राज्य आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाएगें,किंतु सासदों और विधायकों की संख्या उनके वेतन भत्तों और पेंशन से देश के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों की और ध्यान नही दिया जाता। यह कहीं गणना नही होती कि इससे देश पर कितना बोझ पड़ेगा।

सैनिकों की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना इसी वित्तीय पुनर्गठन की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जाती है। अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती किया जाता है, जिसके बाद केवल 25 प्रतिशत को ही स्थायी सेवा में रखा जाता है। शेष 75 प्रतिशत युवाओं को एकमुश्त सेवा निधि पैकेज देकर सेवामुक्त कर दिया जाता है, और उन्हें आजीवन पेंशन या अन्य चिकित्सा सुविधाएं नहीं दी जातीं। सरकार का उद्देश्य रक्षा बजट के एक बड़े हिस्से को, जो वर्तमान में वेतन और पेंशन में चला जाता है, आधुनिक हथियारों और तकनीक की खरीद में लगाना है। लेकिन इस योजना ने सुरक्षा विशेषज्ञों और युवाओं के बीच चिंता पैदा कर दी है। आलोचकों का कहना है कि पेंशन के अभाव में सैनिकों का मनोबल प्रभावित हो सकता है और चार साल बाद बेरोजगार होने का डर युवाओं को इस गौरवशाली पेशे से दूर कर सकता है।

एक तरफ जहां देश की सुरक्षा और प्रशासनिक सेवा में लगे लोगों के लाभों को सीमित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर 131वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटों को बढ़ाकर लगभग 815 से 850 तक करने का प्रस्ताव है।इसी के साथ नए परीसीमन से विधायकों की भी 2045 सीट बढ़ने की व्यवस्था है। यह वृद्धि परिसीमन की प्रक्रिया के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व को संतुलित करना है। हालांकि यह कदम लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से तर्कसंगत लग सकता है, पर इसके आर्थिक निहितार्थ अत्यधिक गंभीर हैं। सांसदों की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि का अर्थ है उनके वेतन, भत्तों, आवास, सुरक्षा और कार्यालय खर्चों में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होना।

यदि हम वर्तमान वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण करें, तो एक सांसद का वेतन और विभिन्न भत्ते मिलाकर प्रतिमाह एक बड़ी राशि बनती है। वर्ष 2025-26 के संशोधित आंकड़ों के अनुसार, एक सांसद का मूल वेतन लगभग 1.24 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र भत्ता (लगभग 70,000 रुपये), कार्यालय भत्ता (लगभग 60,000 रुपये) और संसद सत्र के दौरान प्रतिदिन का दैनिक भत्ता (2,500 रुपये) मिलता है। यदि इन सबको जोड़ दिया जाए, तो एक सांसद पर सीधे तौर पर प्रतिमाह लगभग 2.7 लाख से 3 लाख रुपये का खर्च आता है। इसमें उनके लिए उपलब्ध मुफ्त बिजली (50,000 यूनिट), पानी (4,000 किलोलीटर), 34 मुफ्त हवाई यात्राएं, रेल यात्राएं और दिल्ली में मिलने वाले महंगे बंगलों का रखरखाव शामिल नहीं है। यदि लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाती है, तो केवल इन सीधे खर्चों के कारण देश पर प्रतिमाह करोड़ों रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।विधायकों की सीट बढ़ने से होने वाला आर्थिक बोझ इसमें शामिल नही किया गया। इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ का अनुमान लगाने के लिए यदि हम 273 नए सांसदों (816 - 543) को आधार मानें, तो केवल उनके वेतन और नियमित भत्तों पर ही प्रतिमाह लगभग 7.5 करोड़ से 8 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा। वार्षिक आधार पर यह आंकड़ा 90 करोड़ से 100 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है। लेकिन यह तो केवल हिमशैल का सिरा है। प्रत्येक नए सांसद के लिए लुटियंस दिल्ली जैसे महंगे इलाकों में आवास की व्यवस्था करना, उनके कार्यालयों का निर्माण और उनके साथ तैनात होने वाले सुरक्षा कर्मियों व सहायक कर्मचारियों का वेतन इस खर्च को कई गुना बढ़ा देगा। इसके अलावा, सांसदों को मिलने वाली आजीवन पेंशन का खर्च भी भविष्य के बजटों पर एक स्थायी बोझ बन जाएगा।

विवाद का मुख्य बिंदु यही है कि जब देश के सैनिकों और आम कर्मचारियों के लिए 'राजकोषीय अनुशासन' और 'पेंशन सुधार' की बात की जाती है, तो वही मापदंड जनप्रतिनिधियों पर लागू क्यों नहीं होते? अग्निवीर योजना के माध्यम से करोड़ों रुपये बचाने की कोशिश करने वाली सरकार जब सांसदों की फौज बढ़ाने की तैयारी करती है, तो आम नागरिक के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या देश की प्राथमिकताएं सही दिशा में हैं। एक तरफ एक जवान है जो अपनी जवानी के चार साल देश को देता है और बिना पेंशन के घर लौट आता है, और दूसरी तरफ एक सांसद है जो केवल पांच साल के कार्यकाल के बाद आजीवन पेंशन और सुविधाओं का हकदार बन जाता है। एक बात और जहां कर्मचारी को पेंशन का हकदार बनने के लिए 20 से 25 साल की सेवा अनिवार्य है, वहां सांसद या विधायक के लिए ऐसा नही है। एक दिन के लिए सांसद या विधायक बनने पर उन्हें पूरी पेंशन मिलती है। सांसद या विधायक जितनी बार चुना जाता है, उसकी उ पेंशन में बढ़े कार्यकाल के हिसाब से वृद्धि मिलती है।कोई व्यक्ति यदि चार बार सांसद और तीन बार विधायक बने तो उसे सांसद काल की चार और विधायक काल की तीन वृद्धि पेंशन में जुड़कर मिलती है। वर्तमान पंजाब सरकार ने एक आदेश करने विधायक के लिए सिर्फ एक पेंशन की व्यवस्था रखी है। ऐसा पूरे देश में क्यों नही हो सकता। सांसद और विधायकों के साथ भी ऐसा ही किया जाना चाहिए।

भारत जैसे विकासशील देश में जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए संसाधनों की भारी कमी है, वहां विधायी विस्तार के खर्चों को बहुत सावधानी से तौलने की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे इस तरह से लागू किया जाना चाहिए कि यह आम जनता के त्याग और सैनिकों के समर्पण के साथ न्याय करे। यदि सरकार को वास्तव में राजकोषीय घाटे की चिंता है, तो उसे सांसदों के वेतन-भत्तों में भी कटौती करने और 'एक राष्ट्र, एक पेंशन' जैसी व्यवस्था पर विचार करना चाहिए, ताकि देश का पैसा सांसदों की सुख-सुविधाओं के बजाय उन लोगों पर खर्च हो जो वास्तव में देश की नींव को मजबूत करते हैं।

अशोक मधुप

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

उचित दर विक्रेताओं ने खोला मोर्चा: जूट बोरा लाभांश न मिलने पर जताई नाराजगी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के राशन डीलरों (उचित दर विक्रेताओं) ने सरकार द्वारा जूट बोरा लाभांश (Jute Bag Margin) का भुगतान न किए जाने पर गहरा रोष व्यक्त किया है। 'ऑल इण्डिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन, उ0प्र0' ने इस संबंध में प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग को पत्र लिखकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है।

भुगतान में देरी: एसोसिएशन का कहना है कि वर्तमान निर्देशों के अनुसार, विक्रेता मार्च और अप्रैल 2026 के खाली जूट बोरे ब्लॉक गोदामों में जमा कर रहे हैं। हालांकि, मार्च 2026 के जमा किए गए बोरों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। विक्रेताओं में असंतोष:भुगतान न होने के कारण डीलरों में भारी नाराजगी है। उन्हें डर है कि पूर्व की भांति इस बार भी उनके लाभांश का भुगतान रोक दिया जाएगा।

कार्य पर प्रभाव: लाभांश न मिलने के कारण डीलरों ने अप्रैल माह के खाली बोरे जमा करने में रुचि लेना कम कर दिया है, जिससे विभागीय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। एसोसिएशन की मांग: संगठन ने प्रमुख सचिव से अनुरोध किया है कि मार्च 2026 के जूट बोरा लाभांश के तत्काल भुगतान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए, ताकि भविष्य में विक्रेता सुचारू रूप से अपना कार्य जारी रख सकें। यह पत्र प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी और प्रदेश महासचिव अशोक सिंह के नेतृत्व में जारी किया गया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि यदि समय पर भुगतान नहीं हुआ तो विक्रेताओं का मनोबल गिरेगा।

जनगणना हेतु मोहनलालगंज में दी गई ट्रेनिंग

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में जनगणना 2027 के अंतर्गत गणना हेतु नगर पंचायत मोहनलालगंज कार्यालय के प्रांगण में प्रगणक एवं सुपरवाइजर प्रशिक्षण का कार्यक्रम विगत 21 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है जहां पर लगातार दो चरणों में 27 अप्रैल तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन दोनों चरणों में मोहनलालगंज क्षेत्र के विविध विभाग के कर्मचारी सम्मिलित हुए जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल थे। यह कार्यक्रम लगातार 6 दिनों तक चलेगा, प्रशिक्षण के दौरान प्रथम चरण में मकान की गणना के बारे में बताया गया । हाउस लिस्टिंग ऐप (एचओएल) ऐप के माध्यम से मकान की गणना करने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान अध्यक्ष राजेश कुमार मोहनलालगंज, अधिशासी अधिकारी अंकिता देवी के साथ कार्यालय के समस्त स्टाफ मौके पर मौजूद थे। जिन्होंने प्रगणक एवं सुपरवाइजर की जनगणना समस्याओं को सुन उनका समाधान भी निकाला गया।

दगा दे गया दूल्हा, बारात का इंतज़ार करती रही दुल्हन

खुलासे ने तोड़ दिए सारे सपने,शहनाई की जगह पसरा सन्नाटा

लालगंज (रायबरेली)। सरेनी के रासीगांव में एक परिवार की खुशियां चंद घंटों में मातम में बदल गईं। जहां शहनाई गूंजनी थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। सजी-धजी दुल्हन चौखट पर बैठी पूरी रात बारात का इंतज़ार करती रही। उसकी नजरें बार-बार उस रास्ते पर टिक जातीं, हर आहट पर उसे लगता कि बारात आ गई... लेकिन रात गुजर गई और इंतजार अधूरा ही रह गया। गेस्ट हाउस में सजे मंडप, माला और खाली पड़ी कुर्सियां उस अधूरी शादी की खामोश गवाही दे रही हैं। मेहमानों के बीच सन्नाटा है और रिश्तेदारों के चेहरों पर कई सवाल तैर रहे हैं। जब सच्चाई सामने आई कि दूल्हा पहले ही किसी और से शादी कर चुका है, तो पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुल्हन की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। भाई ने बताया कि उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी की तैयारी की थी और करीब 10 लाख रुपये खर्च कर दिए थे। परिवार का कहना है कि यह सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं, बल्कि भरोसे के टूटने का गहरा घाव है। परिजन बार-बार बेटी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सदमे की स्थिति साफ झलक रही है। गांव के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं और इसे बेटी के साथ बड़ा अन्याय बता रहे हैं। फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय की आस में है। दुल्हन ने सरेनी कोतवाली में तहरीर दे दी है। प्रभारी निरीक्षक रमेश चंद्र यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

थाने के सामने से रातों-रात उखाड़ा गया महाराजा मलिहा पासी स्मृति द्वार, प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल, मलिहाबाद में दिनभर उबाल पर रहा माहौल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मलिहाबाद, लखनऊ: मलिहाबाद क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। थाने से महज 10 मीटर की दूरी पर स्थापित महाराजा मलिहा पासी स्मृति द्वार को अज्ञात लोगों द्वारा रातों-रात उखाड़कर गायब कर दिया गया। यह घटना उस स्थान पर हुई जहां सुरक्षा के लिहाज से सबसे अधिक सतर्कता अपेक्षित होती है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी, जिससे लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। जानकारी के अनुसार यह स्मृति द्वार क्षेत्र की मौजूदा विधायक जयदेवी कौशल द्वारा लगवाया गया था, जो पासी समाज के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। जैसे ही सुबह लोगों को इस द्वार के गायब होने की जानकारी मिली, क्षेत्र में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। घटना से आहत पासी समाज के लोगों में गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दिया और उन्होंने तत्काल विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

प्रदर्शन धीरे-धीरे व्यापक रूप लेता गया और पूरे दिन मलिहाबाद का माहौल गरमाया रहा। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और

इस घटना की कड़ी निंदा की। सुहेलदेव आर्मी के चीफ योगेश पासी, लाखन आर्मी के चीफ सूरज पासी, रक्षपार्टी के आर.के. आदर्श सहित कई प्रमुख लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके अलावा बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, आशु किशोर और ब्लॉक प्रमुख मीनू वर्मा ने भी मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करने का प्रयास किया और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। प्रशासन की ओर से इस मामले में सफाई दी गई कि जिस कंपनी ने स्मृति द्वार का निर्माण कराया था, उसका भुगतान अभी तक पूरा नहीं किया गया था। इसी कारण कंपनी ने रात में आकर द्वार को उखाड़ लिया।

हालांकि यह दलील लोगों के गले नहीं उतर रही है। लोगों का कहना है कि यदि भुगतान का मामला था तो इसे कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत सुलझाया जाना चाहिए था, न कि चोरी-छिपे इस तरह की कार्रवाई की जाती। साथ ही यह भी सवाल उठ रहा है कि इतनी संवेदनशील जगह पर बिना किसी अनुमति के इतनी बड़ी संरचना को कैसे हटाया जा सकता है।

घटना ने सामाजिक एकजुटता की भी एक मिसाल पेश की, जब ब्राह्मण समाज के शुभम पंडित ने खुलकर पासी समाज के समर्थन में आवाज उठाई। इससे यह स्पष्ट हुआ कि यह मामला केवल एक समाज तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि व्यापक स्तर पर लोगों की भावनाएं इससे जुड़ गई हैं। वहीं कुछ अन्य समाज के लोगों द्वारा पहले से इस स्मृति द्वार का विरोध किए जाने की बात भी सामने आई है, जिससे मामले ने और अधिक तूल पकड़ लिया है।

प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पासी समाज के संगठनों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक महाराजा मलिहा पासी स्मृति द्वार को पुनः स्थापित नहीं किया जाता और इस घटना के जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को आश्वासन दिया है कि शाम तक स्मृति द्वार को दोबारा स्थापित कर दिया जाएगा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यह घटना न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि संवेदनशील मुद्दों को समय रहते संभालना कितना आवश्यक है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं कि वह इस पूरे मामले को किस तरह सुलझाता है और लोगों का भरोसा दोबारा जीत पाता है या नहीं।

5 साल से केजीएमयू में सक्रिय था फर्जी डॉक्टर हस्साम, 2023 में हुई थी पिटाई; पूछताछ में हुए चौंकाने वाले खुलासे

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

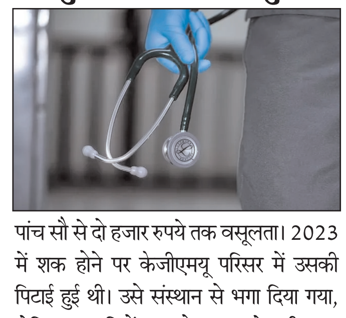

लखनऊ। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) से पकड़े गए खुद को एमबीबीएस डॉक्टर बताने वाले हस्साम अहमद से पुलिस की पूछताछ में कई राजफाश हुए हैं। पूछताछ में उसने बताया कि वह 2021 से संस्थान परिसर में सक्रिय था। वह इसी बैच का एमबीबीएस पास आउट होने का दावा करता था। मरीजों को चिकित्सकों से ओपीडी में दिखाने के नाम पर दो हजार रुपये तक वसूल लेता था। 2023 में उसे कुछ लोगों ने पीटा था। उसके पास से पुलिस को एक मोबाइल फोन, एक आईपैड मिला है। पुलिस अब सीडीआर की मदद से जांच कर रही है। सिद्धार्थ नगर के मोहाना स्थित ककरावा निवासी मोहम्मद हस्साम मड़ियांव के अजीज नगर में अपनी चचेरी अप्पी के घर में रहता था। 13 अप्रैल 2026 को उसने सर्जरी विभाग के प्रोफेसर व डीन पैरामेडिकल डॉ. केके सिंह के फर्जी हस्ताक्षर से एक नोटिस जारी की थी। इसमें एमबीबीएस 2023 बैच के विद्यार्थियों को 29 अप्रैल को एम्स दिल्ली में होने वाली एक कान्फ्रेंस में शामिल होने का निर्देश दिया गया था। जांच में नोटिस फर्जी पाया गया तो उसकी गतिविधियों पर शक गया। इसी के बाद फर्जीवाड़ा सामने आया। बुधवार को चौक पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद आरोपित को जेल भेज दिया। पूछताछ में उसने बताया कि 2021 से वह संस्थान में डॉक्टर बनकर घूमता था। सफेद एप्रन, आला पहनकर वह संस्थान के किसी भी विभाग में पहुंचता फिर उन मरीजों को निशाना बनाता जो गंभीर होते थे। डॉक्टर को दिखाने के नाम पर वह प्रत्येक मरीज से पांच सौ से दो हजार रुपये तक वसूलता। 2023 में शक होने पर केजीएमयू परिसर में उसकी पिटाई हुई थी। उसे संस्थान से भगा दिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद दोबारा उसने वही काम शुरू कर दिया। लंबे समय से संस्थान में गैर कानूनी रूप से घूमने के बावजूद उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला, इससे संस्थान की आंतरिक सुरक्षा और चौकसी पर भी सवाल उठ रहा है। पुलिस को उसके पास से मिले मोबाइल और आईपैड से कई जानकारियां मिली है। जांच में कई चिकित्सकों से उसकी चैटिंग मिली है। हस्साम के मोबाइल नंबर की सीडीआर भी निकलवाई जा रही है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम कमलेश दीक्षित ने बताया कि आरोपित को जेल भेजा गया है। अन्य बिंदुओं पर जांच जारी है।

हस्साम ने कई एनजीओ बनाई थी और इन की आड़ में मरीजों से संपर्क साधता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में उसकी चार एनजीओ होने की बात पता चली है। एनजीओ को विदेशी फंडिंग की भी आशंका है। केजीएमयू के हर विभाग में उसका दखल था। एक विभाग के तकनीनिशियन की मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है। उधर, मंगलवार रात पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। बैरक में उसने खाना खाने से इंकार किया।

विश्व पृथ्वी दिवस पर भरवारा एसटीपी में पौधरोपण: हरियाली बढ़ाने को सुएज का संकल्प

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर भरवारा स्थित 345 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में 'वन सिटी, वन ऑपरेटर' पहल के अंतर्गत कार्य कर रही संस्था सुएज ने आइवा के साथ मिलकर पौधरोपण किया। इस दौरान परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष 22 अप्रैल को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिन लोगों को यह संदेश देता है कि प्लास्टिक के उपयोग को कम करें और अधिक से अधिक पेड़ लगाकर पृथ्वी को सुरक्षित बनाएं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सुएज द्वारा यह पहल की गई। सुएज लखनऊ में सस्टेनेबिलिटी को लेकर अत्यंत सजग है और भरवारा एसटीपी परिसर को हरा-भरा बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत है। कंपनी द्वारा समय-समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। इस अवसर पर परियोजना निदेशक राजेश मठपाल ने कहा, 'पृथ्वी दिवस हमें पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। सुएज सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। पौधरोपण जैसे छोटे प्रयास भी आने वाले समय में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमारा उद्देश्य केवल संचालन तक सीमित नहीं, बल्कि प्रकृति के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी करना भी है। कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि यदि प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण की दिशा में छोटे-छोटे कदम उठाए, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है।

पैदल मार्च कर पुलिस ने दिया सुरक्षा का भरोसा

लालगंज (रायबरेली)। नगर में बुधवार को पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पैदल मार्च निकाला। इंस्पेक्टर क्राइम अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिसकर्मी सड़कों पर उतरे। पुलिस ने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। मार्च बेटा चौराहा से शुरू होकर आचार्य नगर रोड होते हुए नई बाजार तक पहुंचा। इस दौरान पुलिस टीम ने बाजार और प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया।पुलिसकर्मियों ने नागरिकों से संवाद किया। लोगों से अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। इंस्पेक्टर ने कहा कि नगर की शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। इसके लिए पुलिस हर समय सक्रिय है। मार्च के दौरान दुकानदारों और राहगीरों ने भी पुलिस से बातचीत की। लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संतोष जताया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर नितिन मलिक, रणजीत कुमार, वीरेंद्र यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

महमूदाबाद में ट्रैफिक सिस्टम फेल, जाम अतिक्रमण और डायवर्जन से शहर बेहाल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महमूदाबाद-सीतापुर शहर की यातायात व्यवस्था इन दिनों पूरी तरह चरमराई हुई है। महमूदाबाद बस स्टैंड, रामकुंड चौराहा और महिला अस्पताल के आसपास हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। आए दिन लगने वाले भीषण जाम ने स्थानीय नागरिकों, मरीजों और यात्रियों की परेशानी कई गुना बढ़ा दी है। हाल ही में रोडवेज बस स्टेशन के पास महिला अस्पताल के निकट घंटों लंबा जाम लगा रहा। स्थिति इतनी गंभीर थी कि वाहन तो दूर, पैदल निकलना भी चुनौती बन गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो पत्रकार अंजू सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया, जिसमें प्रशासन की निष्क्रियता साफ नजर आई। बस स्टैंड और प्रमुख चौराहों पर अवैध ठेले और कब्जों ने सड़कें संकरी कर दी हैं।

रोडवेज के पास प्राइवेट बस और टैक्सी स्टैंड सड़क पर ही संचालित हो रहे हैं, जिससे ट्रैफिक बाधित होता है। पहले हटाए गए अतिक्रमण फिर से लौट आए हैं, जिससे

हालात जस के तस बने हुए हैं। नगर पालिका और तहसील प्रशासन पर आरोप है कि वे केवल औपचारिक कार्रवाई तक सीमित हैं। अतिक्रमण हटाने के नाम पर दिखावटी कार्रवाई जाम नियंत्रित करने में नाकामी

पुलिस तैनाती के बावजूद ट्रैफिक कंट्रोल नहीं

यहां तक कि एक पूर्व EO का जाम को लेकर 'बेबसी' वाला बयान भी वायरल हो चुका है, जो व्यवस्था की पोल खोलता है। बाराबंकी-बहराइच हाईवे (NH-927) पर घाघरा नदी के संजय सेतु (रामनगर) की मरम्मत के चलते 16 अप्रैल 2026 से भारी वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया है।

चहलारी घाट और अन्य मार्गों से गुजरते ट्रक अब महमूदाबाद की सड़कों पर आ रहे हैं संकरी सड़कों पर भारी वाहनों का दबाव कई गुना बढ़ गया है कई बार एंबुलेंस जाम में फंस रही हैं, जिससे मरीजों की जान खतरे में पड़ रही है

बाजार में खरीदारी और आवाजाही मुश्किल हो गई है

व्यापारियों और आम लोगों में भारी नाराजगी

स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस मिलकर ठोस और स्थायी योजना नहीं बनाते, तब तक यह समस्या और विकराल होती जाएगी। अब बड़ा सवाल यही है- क्या जिम्मेदार अधिकारी जागेंगे या महमूदाबाद यूं ही जाम में जूझता रहेगा?

लखनऊ में चॉकलेट दिलाने के बहाने अधेड़ ने पांच साल की बच्ची से की छेड़छाड़, गिरफ्तार

लखनऊ। महानगर पुलिस ने पांच वर्षीय बच्ची को चाकलेट दिलाने के बहाने सुनसान जगह ले जाकर छेड़छाड़ करने वाले 56 वर्षीय आरोपित को गिरफ्तार किया है। बुधवार को पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। एक कालोनी निवासी महिला ने मंगलवार को थाने में तहरीर देकर बताया कि अकबरनगर बंधा स्थित सचिवालय कालोनी निवासी छेदीलाल उनकी पांच वर्षीय बेटी को चाकलेट दिलाने के बहाने अपनी स्कूटी पर बैठा ले गया। तिकोनिया पार्क के पास एक झोपड़ी में बनी कपड़े प्रेस करने वाली दुकान के अंदर ले जाकर उसने बेटी के साथ अश्लीलता की और निजी अंगों को गलत नीयत से छुआ। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। बेटी ने रोना शुरू किया तो आरोपित उसे वापस घर के पास छोड़ गया। किसी तरह बेटी घर पहुंची। उसे गुमसुम देखा तो मां ने कारण पूछा। कई बार पूछने पर उसने पूरी घटना बताई। यह सुनकर परिवारजन के होश उड़ गए। उन्होंने महानगर थाने में आरोपित के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। अतिरिक्त निरीक्षक प्रदीप सिंह ने बताया कि छेदीलाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

यूपी में सात मई से शुरू होगी स्वगणना, 22 से फील्ड में उतरेंगे 5.27 लाख कर्मी

- 7 मई से 21 मई तक स्वगणना की सुविधा रहेगी।

22 मई से 5.27 लाख कर्मी फील्ड में उतरेंगे।

एचएलबीसी पोर्टल पर जिलों की मैपिंग जारी है।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। जनगणना 2027 के लिए प्रदेश में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। सात मई से 21 मई तक लोगों को स्वगणना की सुविधा रहेगी। इसके बाद 22 मई से 20 जून के बीच पहले चरण में घरों की गणना व सीमांकन के लिए करीब 5.27 लाख प्रगणक और सुपरवाइजर फील्ड में उतरेंगे। इससे पहले एचएलबीसी (हाउस लिस्टिंग ब्लाक क्रिएटर) पोर्टल पर जिलों की मैपिंग पूरी होने वाली है।

इस पोर्टल के जरिये घर- घर की गणना के लिए मकानों के डिजिटल ब्लाक बनाए जा रहे हैं, उनकी सीमाएं तय की जा रही हैं और नक्शे तैयार किए जा रहे हैं। शेष

मैपिंग कार्य अगले दो दिनों में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बुधवार को मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर जनगणना की निगरानी के लिए जनगणना प्रबंधन और निगरानी (सीएमएमएस) पोर्टल के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया।

उन्होंने स्वगणना को बढ़ावा देने, जिलों में वाट्सएप समूह बनाकर समस्याओं का तुरंत समाधान करने और संसाधनों के बेहतर उपयोग के निर्देश दिए। साथ ही प्रशिक्षण, फील्ड विजिट और बैठकों की जानकारी सार्वजनिक करने और हैशटैग के उपयोग की भी बात कही। जिला जनगणना सेल को एनआईसी और डीईएसटीओ के साथ मिलकर कंट्रोल रूम के रूप में सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में स्वगणना बढ़ाने और कम भागीदारी वाले क्षेत्रों में हेल्पलाइन शुरू करने को कहा गया है।

निदेशक जनगणना शीतल वर्मा के अनुसार, 31 जिलों में मैपिंग का काम पूरी तरह पूरा हो चुका है। 33 जिलों में यह 98 से 99.99 प्रतिशत तक, सात जिलों में 90 से 98 प्रतिशत, दो जिलों में 80 से 90 प्रतिशत और दो जिलों में 80 प्रतिशत से कम पूरा हुआ है। नेशनल, मास्टर और फील्ड ट्रेनर्स का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। अब लगभग 5.27 लाख प्रगणक और सुपरवाइजर्स का प्रशिक्षण पांच मई तक चलेगा। पहले चरण में नियुक्ति, प्रशिक्षण और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी एसडीएम को दी गई है, जबकि स्वगणना की रणनीति सीडीओ और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की देखरेख में तैयार की जा रही है।

विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर जागरूकता शिविर का आयोजन संपन्न

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रायबरेली:- उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमित पाल सिंह के निर्देशानुसार व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली अनिशा के दिशा-निर्देशन में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर राजकीय इण्टर कालेज रायबरेली में विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर मे डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउंसिल जय सिंह यादव के द्वारा उपस्थित छात्रों को निःशुल्क विधिक सहायता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया गया कि पृथ्वी दिवस पर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिससे पर्यावरण संतुलित रहे यह हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। उक्त अवसर पर पराविधिक स्वयं सेवक पवन कुमार श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए उपस्थित छात्र-छात्राओं को बताया गया पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाए जाने वाला एक वैश्विक आयोजन है जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी पृथ्वी दिवस 2026 की थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह यह थीम स्वच्छ ऊर्जा को तेज करने और सामुदायिक स्तर पर समाधानों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई पर जोर देती है।

इस कार्यक्रम में राजकीय इंटर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य प्रत्यूष श्रीवास्तव, अध्यापक गण डॉ हरिओम त्रिपाठी, प्रीतम कुमार, दिव्य प्रकाश श्रीवास्तव, धर्मेंद्र शुक्ला द्वारा भी उपस्थित छात्र-छात्राओं को विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर जानकारी प्रदान की गयी। उक्त जागरुकता कार्यक्रम में पराविधिक स्वयंसेवक मनोज कुमार प्रजापति व भारी संख्या में स्कूली छात्र-छात्रा मौजूद रहे। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर जनपद रायबरेली की तहसील महाराजगंज, लालगंज, सलोन, डलमऊ, ऊंचाहार वह जनपद अमेठी की तहसील तिलोई में भी विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

देवरिया में जिला कार्यक्रम प्रबंधक की रहस्यमयी मौत, सड़क किनारे खड़ी कार में अचेत मिले

देवरिया। डीपीआरओ कार्यालय में जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) की बुधवार की देर शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। वह चीनी मिल मैदान के समीप कार में अचेत पड़े थे। शीशा तोड़कर बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बरहज थाना क्षेत्र के दुबौली गांव के रहने वाले 40 वर्षीय जितेंद्र दुबे शहर के उमा नगर मोहल्ले में परिवार के साथ किराये के मकान में रहते थे। शाम करीब छह बजे वह कार्यालय से घर जाने के लिए कार से निकले।

चीनी मिल मैदान के पास उन्होंने सड़क किनारे कार खड़ी कर दी और काफी देर तक उसी में बैठे रहे। लंबे समय तक कोई गतिविधि न दिखने पर आसपास के दुकानदारों को संदेह हुआ व उन्होंने रात करीब साढ़े आठ बजे पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। कार का शीशा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला गया व तत्काल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। क्षेत्राधिकारी सदर संजय कुमार रेड्डी ने आसपास के लोगों से पूछताछ की व घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। उधर, सूचना मिलते ही स्वजन भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंच गए, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल था। सीओ ने बताया कि मृत्यु के कारणों का स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।

यूपी RTE में 1.95 लाख में सिर्फ 56 प्रतिशत हुआ एडमिशन, DM को 25 अप्रैल तक प्रवेश कराने का निर्देश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश में गरीब और वंचित बच्चों को निजी स्कूलों तक पहुंच दिलाने वाली आरटीई एक्ट (निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम) की प्रगति धीमी नजर आ रही है। 1.95 लाख से अधिक सीटें आवंटित होने के बावजूद अब तक सिर्फ 56 फीसदी बच्चों का ही दाखिला हो पाया है। इस पर शासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी जिलाधिकारियों को 25 अप्रैल तक हर हाल में 100 प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित कराने का अल्टीमेटम दे दिया है।

इस शैक्षणिक सत्र में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के कुल 1,95,740 बच्चों को गैर सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की कक्षा एक और पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में दाखिले के लिए सीटें आवंटित की गई थीं। 20 अप्रैल तक प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित होने के बावजूद अब तक केवल 1,08,866 बच्चों (56 प्रतिशत) का ही दाखिला हो सका है। यह आंकड़ा शासन के लक्ष्य से काफी पीछे है, जिससे विभाग में चिंता बढ़ गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बुधवार को सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी व्यक्तिगत स्तर पर इस प्रक्रिया की निगरानी करें और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित करें कि 25 अप्रैल तक सभी आवंटित बच्चों का प्रवेश हर हाल में पूरा हो जाए। वहीं, दाखिले की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मुख्य सचिव स्तर से भी इसकी नियमित समीक्षा की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की बाधा को तुरंत दूर कर प्रवेश प्रक्रिया को तेज किया जा सके।

संक्षिप्त खबरें

भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए मुहिम: घर-घर रखे जा रहे पानी और दाने के बर्तन

बढ़ती गर्मी ने जहां इंसानों का हाल बेहाल कर दिया है, वहीं पक्षियों के लिए हालात और भी मुश्किल हो गए हैं। तेज तापमान के चलते उन्हें पानी और भोजन ढूंढना कठिन हो रहा है। ऐसे में लोगों द्वारा शुरू की गई एक छोटी पहल अब एक बड़ी मुहिम का रूप लेती जा रही है।

वेस्ट किदवई नगर में पहल

वेस्ट किदवई नगर इलाके में स्थानीय निवासियों ने मिलकर अब तक 100 से ज्यादा मिट्टी के बर्तन अलग-अलग स्थानों पर रख दिए हैं, जिनमें पक्षियों के लिए पानी और दाना उपलब्ध कराया जा रहा है। निवासियों ने आम जनता से भी अपील की है कि वे अपने घर के बाहर कम से कम दो बर्तन–एक पानी और एक खाने के लिए–रखें और उन्हें रोज भरते रहें, ताकि पक्षियों को इस भीषण गर्मी में राहत मिल सके।

गर्मी में बढ़ी चुनौती

तापमान बढ़ने के साथ पेड़-पौधों की कमी और जल स्रोतों के सूखने से पक्षियों के लिए जीवित रहना कठिन होता जा रहा है। ऐसे में यह छोटी-सी कोशिश उनके जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा सकती है।

विश्वकर्मा समाज का प्रदर्शन: निशा विश्वकर्मा को न्याय व पूर्व मंत्री पर हमले के विरोध में सौंपा ज्ञापन

महरौनी। मृतका निशा विश्वकर्मा को न्याय दिलाने एवं अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व शिक्षा मंत्री रामआसरे विश्वकर्मा पर हुए हमले के विरोध में बुधवार को महरौनी तहसील परिसर में विश्वकर्मा समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के उपरांत राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी महरौनी रजनीश बाजपेई को सौंपा गया।

जिलाध्यक्ष महेंद्र झा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाज के लोग तहसील परिसर पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में मृतका निशा विश्वकर्मा को शीघ्र न्याय दिलाने तथा पूर्व मंत्री पर हमला करने वाले दोषियों को सख्त सजा देने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई।

इस दौरान नीलेश झा (जिलाध्यक्ष, झा समाज सैदपुर), भैरोप्रसाद विश्वकर्मा, भगवत प्रसाद विश्वकर्मा, एडवोकेट राजेश विश्वकर्मा (राजू घड़ी), अमृतलाल झा, कल्लू झा (सौरई), सुखदयाल अहिरवार (राष्ट्रीय सचिव, अनुसूचित जाति सपा), ओमकार प्रसाद, संजू वर्मा (जिलाध्यक्ष एससी/एसटी प्रकोष्ठ सपा), अवध बिहारी झा, शिवशंकर विश्वकर्मा (विधानसभा अध्यक्ष भौंडी, महरौनी), चंद्रेश झा (ब्लॉक अध्यक्ष गुढ़ा, महरौनी), शीतल प्रसाद विश्वकर्मा, मनीष विश्वकर्मा, सोनू विश्वकर्मा, कुलदीप झा, करीटोरन, कृष्णकांत झा (अमौरा खैरो), सौरभ झा, आलोक झा, अरविंद झा, मनीष झा, राजाराम झा, सतेंद्र झा, हरीशंकर झा (धवा), राजेश झा, आलोक झा, रामकिशोर झा, रामजी झा, नितिन झा सहित अनेक लोग मौजूद रहे।

कुआतलां प्रधान विजय लोधी ने घर बुलाकर बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा, धमकाया

पंचायत के सामने हुआ हमला, लात-घूंसों से पीटकर घायल किया, गांव में दहशत

ललितपुर। कोतवाली क्षेत्र में दबंगई का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग को ग्राम प्रधान के घर बुलाकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद पीड़ित और उसका परिवार दहशत में है। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुआतला निवासी 62 वर्षीय सीताराम पुत्र कामता प्रसाद ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि गांव के ही विजय लोधी वर्तमान ग्राम प्रधान ने उसे अपने घर बुलवाया था। बताया गया कि 16 अप्रैल 2026 को दोपहर करीब 2 बजे जब सीताराम अपने साथी के साथ ग्राम प्रधान विजय लोधी के घर पहुंचे, तो वहां पहले से ही कई लोग मौजूद थे। इनमें गांव और आसपास के कुछ प्रभावशाली लोग भी शामिल थे। पीड़ित के अनुसार जैसे ही वह घर के अंदर पहुंचा तभी ग्राम प्रधान विजय लोधी ने अचानक लात-घूंसों से हमला कर दिया। उसके बाद अन्य आरोपियों में प्रताप लोधी, अजय लोधी, भानुचंद्र लोधी भी एकजुट होकर मारपीट में शामिल हो गए। इन सभी ने मिलकर सीताराम को बुरी तरह पीटा, जिससे उसके मुंह, कान और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं।

भीषण गर्मी में बिजली कटौती से तड़प रहा पंजाब का हर इंसान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

चंडीगढ़- शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। मजीठिया ने कहा कि इस समय पंजाब में बिजली की मांग 11000 मेगावाट को पार पहुंचने वाली है और पंजाब में मौसम विभाग के कहे मुताबिक हीटवेव की स्थिति बन चुकी है, लेकिन पंजाब स्टेट पावर कोरपोरेशन लिमिटेड बाहरी स्रोतों से बिजली खरीदने में बुरी तरह विफल हो रहा है। इसके साथ ही राज्य के कई उत्पादन यूनिट भी कथित रूप से बंद होने की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल पैदा होना शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि 'तपते घरों में इस समय पंजाब के लोग रह रहे है , अंधेरे ओर लंबे पावर कटो में रो रहे है–ओर सरकार विदेशों में आराम कर रही है भीषण गर्मी के साथ बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन पंजाब सरकार ने 'ऑपरेशन कवर-अप' शुरू कर लोगों को भ्रम में रखा हुआ है कि पंजाब स्टेट पावर कोरपोरेशन लिमिटेड के पास पर्याप्त अतिरिक्त बिजली है। हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। पूरे पंजाब में लंबे-लंबे बिजली कटों ने हाहाकार मचा दिया है और सरकार के दावों की पोल खोल दी है। जो कहते थे कि उन्होंने 'पावर कट-लेस पंजाब' बना दिया है, वे जमीनी हकीकत देखें–हर तरफ बिजली कट ही कट हैं। इस समय पंजाब के लोग भीषण गर्मी में त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, जबकि भगवंत मान अपने मंत्री संजीव अरोड़ा के साथ विदेशों की ठंडी वादियों में आनंद ले रहे हैं ओर गिलासी खड़का रहे है। उन्होंने पी एस पी सी एल से मांग की कि पंजाब के लोगों को बिजली की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाए ताकि बढ़ती गर्मी के बीच लोग वैकल्पिक इंतजाम कर सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली बोर्ड की कीमती जमीनों को अंदरखाते अपने चहेतों को कौड़ियों के भाव बेचने की तैयारी की जा रही है, जो पंजाब के खजाने के साथ सीधा धोखा है।

उन्होंने कहा कि अकाली दल सरकार ने नए थर्मल प्लांट लगाकर पंजाब को बिजली सरप्लस राज्य बनाया था और 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की थी। खेती, उद्योग और आम लोगों को लगातार बिजली मिलती थी! उन्होंने मांग की कि पंजाब के लोगों को बिजली की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाए ताकि बढ़ती गर्मी के बीच लोग वैकल्पिक इंतजाम कर सकें। उन्होंने कहा कि एक ओर आम जनता 12-12 घंटे की बिजली कटौती झेलने को मजबूर है, वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान और बिजली मंत्री विदेशों में ठंडी जगहों पर अपने करीबियों के साथ आनंद ले रहे हैं। मजीठिया ने कहा कि ईडी को बिजली मंत्री द्वारा बिजली बोर्ड की जमीनों के जरिए मिलीभगत से राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाने और अपने चहेतों को लाभ देने के आरोपों की जांच करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन जमीनों को सस्ते में बेचकर बड़े घोटाले की तैयारी की जा रही है और इसमें उच्च स्तर की मिलीभगत की आशंका है। उन्होंने कहा कि जब सरकार अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी जमीनें तक बेचने लगे, तो ऐसे माहौल में निवेश और उद्योग कैसे आएगा? सिद्धू मूसेवाला मामले पर मजीठिया ने कहा कि किसी भी अपराधी को फिल्मों या डॉक्यूमेंट्री के जरिए हीरो के रूप में पेश करना गलत है। उन्होंने कहा कि यदि कोई सीरीज बनती है तो उसमें यह भी दिखाया जाना चाहिए कि लॉरेंस के साथ किन-किन लोगों की मिलीभगत थी और कैसे सुरक्षा हटाने की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद मूसेवाला को निशाना बनाया गया।

अमृतपाल सिंह पर एनएसए हटाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अकाली दल हमेशा मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जवाब राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार को देना चाहिए, जिन्होंने मिलकर कार्रवाई की थी। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा नशों को लेकर की गई गलत बयानबाजी पर माफी मांगी जा चुकी है और जो बाकी लोग हैं, वे भी जल्द सच्चाई स्वीकार करेंगे।

सिंहस्थ शाही स्नान में बड़ा बदलाव: उज्जैन स्टेशन पर नहीं आएंगी ट्रेनें, फ्लैग स्टेशनों से बसों में घाट तक पहुंचेंगे श्रद्धालु

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उज्जैन – उज्जैन में आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले को लेकर प्रशासन और रेलवे ने भीड़ प्रबंधन के लिए बड़ा निर्णय लिया है। शाही स्नान और प्रमुख पर्वों के दौरान अब ट्रेनें सीधे उज्जैन रेलवे स्टेशन तक नहीं आएंगी। इसके स्थान पर ट्रेनों को शहर के आसपास स्थित फ्लैग स्टेशनों पर रोका जाएगा, जहां से श्रद्धालुओं को बसों के माध्यम से शिप्रा नदी के घाटों तक पहुंचाया जाएगा। गुरुवार को रेलवे और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त टीम ने प्रस्तावित व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। रतलाम से विशेष सैलून के माध्यम से पहुंचे अधिकारियों में एडीआरएम अक्षय कुमार, एडीजी राकेश गुप्ता, संभागायुक्त आशीष सिंह, कलेक्टर रौशन सिंह, डीआईजी नवनीत भसीन और एसपी प्रदीप शर्मा शामिल रहे। टीम ने पंवासा, नईखेड़ी, पिंगलेश्वर, मोहनपुरा, विक्रमनगर और चिंतामन स्टेशनों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान यात्रियों के प्रवेश और निकास मार्ग, भीड़ नियंत्रण व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की गहन समीक्षा की गई। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से घाटों तक पहुंचाया जा सके। मेला प्रशासन ने इन फ्लैग स्टेशनों से घाटों तक विशेष बस सेवाएं संचालित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं रेलवे की ओर से नईखेड़ी स्टेशन पर चार नए प्लेटफॉर्म विकसित करने की योजना है, साथ ही अन्य स्टेशनों पर भी यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इस नई व्यवस्था से भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और शाही स्नान के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सकेगा।

ब्रह्माकुमारीज वरदानी भवन में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग का स्वास्थ्य शिविर

ललितपुर। समाज में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और लोगों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से ब्रह्माकुमारीज संस्था में एक विशेष स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं योग प्रशिक्षकों ने उपस्थित लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, संतुलित आहार लेने तथा नियमित योग और ध्यान करने के महत्व के बारे में बताया। विभाग अध्यक्ष रवि पचौरी ने बताया कि वर्तमान समय में बढ़ते तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण अनेक बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, जिन्हें सही जीवनशैली से रोका जा सकता है। इस दौरान निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर एवं अन्य सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किए गए। प्रतिभागियों को आवश्यकतानुसार दवाइयां दी गई। कार्यक्रम में राजयोगिनी बीके चित्ररेखा दीदीजी ने राजयोग ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति और सकारात्मक सोच विकसित करने के तरीकों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मन की शांति ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है।

नेपाल में प्रदूषण का कहर: काठमांडू बना गैस चैंबर, दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित!

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नेपाल की राजधानी काठमांडू में पिछले 24 घंटों में वायु गुणवत्ता तेजी से खराब हुई है। IQAir के अनुसार, यह शहर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 247 दर्ज किया गया, जो 'बहुत अस्वस्थ' श्रेणी में आता है। इस सूची में Lahore पहले स्थान पर है, जहां AQI 381 दर्ज किया गया, जो बेहद खतरनाक स्तर माना जाता है। AQI 200 से ऊपर होने का मतलब है कि हवा बहुत खराब है और इससे आम लोगों के साथ-साथ संवेदनशील वर्गों को गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हो सकता है। 300 से ऊपर का स्तर तो 'खतरनाक' माना जाता है। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण P M2.5 कण हैं, जो बहुत छोटे होते हैं और सीधे फेफड़ों और खून तक पहुंच सकते हैं। ये लंबे समय तक हवा में बने रहते हैं, जिससे लोगों के बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। Nepal में प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। उद्योगों का धुआं, वाहनों का प्रदूषण, घरों से निकलने वाला धुआं और कचरे को जलाना इसके मुख्य कारण हैं। खराब हालत वाले वाहन भी प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, वायु प्रदूषण के कारण हर साल करीब 42,000 लोगों की मौत होती है। इनमें 19% बच्चे (5 साल से कम उम्र) और 27% बुजुर्ग (70 साल से अधिक) शामिल हैं। इससे लोगों की औसत आयु पर भी असर पड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक ऐसे प्रदूषण में रहने से सांस की बीमारियां, दिल की समस्या और अन्य गंभीर रोग बढ़ सकते हैं। बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग सबसे ज्यादा खतरे में हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे बाहर कम निकलें, मास्क पहनें और सावधानी बरतें। लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए सख्त नियम, बेहतर ट्रैफिक सिस्टम और साफ ऊर्जा के उपाय जरूरी हैं।

वीजा सख्ती के बाद कनाडा का बड़ा यू-टर्न- अब टॉप स्टूडेंट्स पर फोकस, 14 दिन में वीजा का प्लान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

विदेशी छात्रों की घटती संख्या ने कनाडा को अपनी शिक्षा और इमिग्रेशन नीति पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सरकार ने रणनीति बदलते हुए डिप्लोमा और अंडरग्रेजुएट स्तर पर सख्ती बढ़ा दी है, जबकि मास्टर्स और पीएचडी जैसे उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मेधावी छात्रों को आकर्षित करने की दिशा में कदम उठाए हैं।

अब टॉप स्टूडेंट्स पर नजर

नई नीति के तहत कनाडा सरकार का फोकस उन छात्रों पर है जो रिसर्च और उच्च शिक्षा में योगदान दे सकते हैं। इसके लिए वीजा प्रक्रिया को तेज करते हुए पीएचडी आवेदनों को 14 दिनों के भीतर मंजूरी देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही छात्रों को अपने जीवनसाथी और बच्चों को साथ ले जाने की सुविधा भी दी जा रही है।

क्यों बदलनी पड़ी नीति

आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय छात्रों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 2024

में जहां करीब 1.88 लाख स्टडी परमिट जारी हुए थे, वहीं 2025 में यह संख्या घटकर लगभग 94 हजार रह गई। कुल विदेशी छात्रों की संख्या में भी करीब 60% की कमी आई है।

नई सुविधा और राहत

अप्रैल 2026 से लागू होने वाली नई व्यवस्था में:

मास्टर्स और पीएचडी छात्रों को स्टडी परमिट कैप से छूट

प्रांतीय सत्यापन पत्र की जरूरत नहीं

जीवनसाथी को ओपन वर्क परमिट

बच्चों को स्टडी परमिट

पढ़ाई के बाद 3 साल तक वर्क परमिट, जिससे PR (स्थायी निवास) का रास्ता आसान

भारत पर खास फोकस

कनाडा ने भारत के साथ शिक्षा सहयोग को भी मजबूत किया है। 20 से अधिक विश्वविद्यालयों ने भारत दौरे के दौरान नई साझेदारियां की हैं, जिनमें संयुक्त डिग्री, रिसर्च और स्कॉलरशिप प्रोग्राम शामिल हैं।

विदेश जाने में भारतीयों का बढ़ता रुझान

पिछले कुछ वर्षों में विदेश में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 2016 में जहां 6.8 लाख छात्र विदेश गए थे, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 13.35 लाख हो गई। आंध्र प्रदेश और पंजाब इस ट्रेंड में सबसे आगे हैं। हालांकि कनाडा का यह बदलाव साफ संकेत देता है कि अब वह संख्या नहीं, बल्कि क्वालिटी स्टूडेंट्स पर ध्यान देना चाहता है। नई नीति से मेधावी छात्रों के लिए मौके बढ़ेंगे, लेकिन सामान्य कोर्स के छात्रों के लिए रास्ता थोड़ा कठिन हो सकता है।

भारत एक महान देश है और वहां मेरा वेरी गुड फ्रेंड टॉप पर है! 'हेलहोल' विवाद पर ट्रंप की सफाई

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी. दरअसल, ट्रंप ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें भारत और चीन जैसे देशों के लिए 'हेलहोल' यानी नर्क जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ था. इस पर विवाद बढ़ने के बाद अब अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने बड़ा बयान जारी किया है. प्रवक्ता के मुताबिक ट्रंप ने भारत को एक 'महान देश' बताया है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत के शीर्ष नेतृत्व में उनका एक बहुत अच्छा दोस्त बैठा है.

क्या था वो विवादित वीडियो?

दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर माइकल सैवेज का एक वीडियो शेयर किया था. माइकल सैवेज एक मशहूर रूढ़िवादी लेखक और रेडियो होस्ट हैं. उस वीडियो में सैवेज ने अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली

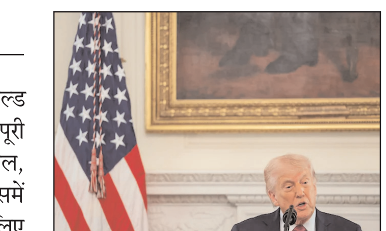

नागरिकता (बर्थराइट सिटीजनशिप) की कड़ी आलोचना की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी लोग अमेरिकी कानूनों का गलत फायदा उठा रहे हैं. सैवेज ने कहा कि लोग अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में अमेरिका आते हैं ताकि उनके बच्चे को वहां की नागरिकता मिल जाए. इसी दौरान उन्होंने भारत और चीन के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था.

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस मामले पर बेहद नपी-तुली प्रतिक्रिया दी है. साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब इस बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बहुत संक्षेप में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि हमने इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं और फिलहाल हम इस पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते. भारत सरकार ने इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने के बजाय कूटनीतिक संयम बनाए रखा है.

माइकल सैवेज ने और क्या आरोप लगाए?

वीडियो में माइकल सैवेज सिर्फ देशों पर ही नहीं बरसे, बल्कि उन्होंने अमेरिकी न्याय प्रणाली और 'अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन' (ACLU) पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कानूनी बहस के नाम पर अमेरिका में अवैध प्रवासियों की बाढ़ लाई जा रही है. उन्होंने तर्क दिया कि नागरिकता जैसे गंभीर मुद्दे पर कोर्ट के बजाय जनता की राय ली जानी चाहिए. उन्होंने मांग की कि बर्थराइट सिटीजनशिप के मुद्दे पर पूरे देश में वोटिंग होनी चाहिए. हालांकि ट्रंप ने अब भारत की तारीफ करके इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की है.

अवैध वसूली मांगने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

तमंचा-कारतूस व मोबाइल बरामद

ललितपुर। थाना जखौरा पुलिस ने अवैध रुपयों की मांग करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, मोबाइल फोन व नकदी बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मु.अ.सं. 108/2026, धारा 308(5) बीएनएस के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया। एसपी मो. मुश्ताक के निर्देशन, एएसपी कालू सिंह व सीओ सदर सुनील कुमार के पर्यवेक्षण में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। थाना जखौरा में 21 अप्रैल 2026 को वादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 20 अप्रैल को कुछ लोगों द्वारा उससे अवैध रुपयों की मांग की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की और टीम गठित की गई। तत्पश्चात 23 अप्रैल को चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने ग्राम सिलगन निवासी गोविन्ददास लोधी पुत्र हरीराम लोधी, सौरभ लोधी पुत्र अमर सिंह लोधी, आर्यन लोधी पुत्र विनोद कुमार, अमोल लोधी पुत्र समरथ लोधी को हिरासत में लिया है।

आपराधिक इतिहास छिपाने वाले आखिर क्यों दे रहे शिक्षक को तरह तरह की धमकी!

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रतापगढ़। पहले आपराधिक इतिहास को छिपाया, फिर उत्सव के दिन लापता होकर रंगत को फीका किया और तो और अब मुकदमे की धौंस देकर आरोपियो द्वारा जबरिया शादी का दबाव एक शिक्षक को खुद न्याय की गुहार लगाने को मजबूर किये हुए है। शिक्षक को चक्रव्यूह में नाधने के लिए दी गई शिकायत भी पुलिस की भी जांच में दूध का दूध पानी का पानी कर गयी है। फिर भी शिक्षक को न्याय के लिए हर चौखट पर दस्तक देनी पड़ रही है। जिले के हथिगवां थाना क्षेत्र के टिकुरी दशरथपुर निवासी राहुल मिश्र कंपोजिट विद्यालय महराजपुर में सहायक अध्यापक पद पर तैनात है। थाना क्षेत्र के ही एक गांव में उसकी शादी तय हुई। बीते वर्ष पचीस नवंबर को शिक्षक के परिजनों ने घर पर तिलक कार्यक्रम की धूमधाम से तैयारी कर रखी थी। तिलक चढ़ाने के लिए देर रात तक दूसरा पक्ष शिक्षक के घर नहीं पहुंचा। इससे गांव इलाके में शिक्षक व उसके परिवार की पगड़ी भी उछली और जमकर छीछालेदर हुई। परेशान शिक्षक व उसके परिवार ने खोजबीन की तब पता चला कि गंभीर धाराओ मे शिक्षक को फंसाने की व्यूह रचना रचने वाले लोग खुद की गंभीर आपराधिक मुकदमें में वांछित होने के कारण तिलक के दिन लापता थे। पीड़ित शिक्षक ने जिले के एसपी को प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि अब दूसरे पक्ष के लोग उस पर जबरिया शादी का दबाव बनाने के लिए दुष्कर्म जैसी संगीन धाराओं में फंसाने और जानलेवा धमकी दे रहे हैं। इस मामले में हथिगवां पुलिस ने भी जांच कर अफसरो को वस्तु स्थिति से अवगत करा रखा है। पीड़ित शिक्षक ने खुद की सुरक्षा के लिए अफसरो से गुहार लगा रखी है।

निःशुल्क कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण हेतु 24 अप्रैल को ब्लाक मानधाता में विशेष पंजीकरण शिविर

प्रतापगढ़। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अभय कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांगजनों और विशेष विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को दैनिक जीवन को सुगम बनाने हेतु अधिकतम रूपये 15,000 तक के कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इन उपकरणों में कृत्रिम हाथ-पैर, कैलिपर्स, ट्राइसाइकिल, बैसाखी, कान की मशीन, व्हीलचेयर, स्मार्टफोन, टैबलेट, ब्रेल किट एवं एडीएल किट आदि शामिल हैं। इच्छुक लाभार्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://divyangjanup.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को हर वर्ष तथा अन्य दिव्यांगजनों को तीन वर्ष में एक बार लाभ देने का प्रावधान है।

बंगाल चुनाव: साल्टलेक से शाह तो कालीघाट से ममता ने संभाली कमान, सभी बूथ पर दोनों की पैनी नजर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कोलकाता। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन गुरुवार को अमित शाह और ममता बनर्जी अपने-अपने वॉर रूम से चुनावी रणनीति को निर्देशित करते नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता के उपनगर साल्टलेक से रियल-टाइम वोटिंग और बूथ-स्तरीय फीडबैक पर नजर रख रहे थे, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शहर के केंद्र कालीघाट से चुनावी गतिविधियों की मानिटरिंग कर रही थीं।

ममता बनर्जी के साथ उनके भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी मौजूद थे। वहीं अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जो बंगाल चुनाव में पार्टी की रणनीति संभाल रहे हैं। सुबह से ही कालीघाट, जो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का प्रमुख राजनीतिक केंद्र है, एक कमांड हब में तब्दील हो गया।

संवेदनशील इलाकों में गड़बड़ी पर लगातार नजर

ममता और अभिषेक बनर्जी मतदान के रुझानों, जिलों से आ रही रिपोर्ट और किसी भी गड़बड़ी के संकेतों पर लगातार नजर बनाए हुए थे। पार्टी सूत्रों के अनुसार, संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही थी और जिला स्तर के नेताओं को लगातार निर्देश दिए जा रहे थे। दूसरी ओर, साल्टलेक स्थित भाजपा कार्यालय में भी समानांतर रणनीतिक नियंत्रण केंद्र सक्रिय रहा। अमित शाह ने मतदान शुरू होने के तुरंत बाद वरिष्ठ नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की और विभिन्न क्षेत्रों से मिल रहे फीडबैक की समीक्षा की।

शाह ने खासतौर पर उत्तर बंगाल पर केंद्रित किया ध्यान

सूत्रों के मुताबिक, अमित शाह ने खासतौर पर उत्तर बंगाल पर ध्यान केंद्रित किया, जो भाजपा के लिए चुनावी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। उन्होंने मतदान प्रतिशत, गड़बड़ी की घटनाओं और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिले इनपुट की गहन समीक्षा की।

पटना में ऑटो ड्राइवर की बेटी की बेरहमी से हत्या! दूध देने गई थी 10 वर्षीय मासूम, कंबल में लिपटा मिला शव

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पटना– राजधानी के बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत बाहरी बेगमपुर मोहल्ले में मानवता को शर्मसार करने वाली एक वारदात सामने आई है. बीते बुधवार से रहस्यमय ढंग से लापता 10 वर्षीय मासूम बच्ची का शव गुरुवार सुबह बेगमपुर स्थित जल्ला वाले हनुमान मंदिर के पास एक गली से बरामद किया गया. बच्ची का शव खून से लथपथ और कंबल में लिपटा हुआ था. जिसे देख पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

दूध देने गई थी, फिर कभी नहीं लौटी

जानकारी के अनुसार बाहरी बेगमपुर निवासी ऑटो चालक और दूध व्यवसायी अनु यादव की पुत्री राजकीय मध्य विद्यालय सती चौड़ा में चौथी कक्षा की छात्रा थी. बुधवार की सुबह वह रोज की तरह अपने पड़ोस में दूध देने गई थी. उसके बाद वह वापस घर नहीं लौटी. परिजनों ने काफी खोजबीन की. जब उसका कहीं अता-पता नहीं चला तो बाईपास थाने में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई. गुरुवार की सुबह घर से कुछ ही दूरी पर उसका शव मिलने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

शरीर पर चोट के निशान, हत्या की आशंका

घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी (पूर्वी) परिचय कुमार, सिटी डीएसपी-2 डॉ. गौरव कुमार, एफएसएल (FSL) और डॉग स्क्वायड की टीमें मौके पर पहुंचीं. पुलिस के अनुसार मृतका के शरीर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं. शव को जिस तरह से कंबल में लपेटकर मंदिर के पीछे वाली गली में फेंका गया. उससे साफ जाहिर होता है कि अपराधियों ने बेरहमी से हत्या करने के बाद साक्ष्य छिपाने की कोशिश की है.

पड़ोसियों पर शक, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी

मृतका की मां विभा देवी ने अपनी व्यथा सुनाते हुए पड़ोस के ही कुछ लोगों पर हत्या की आशंका जताई है. पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है. सिटी एसपी परिचय कुमार ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद कहा कि पुलिस सभी बिंदुओं पर गहन छानबीन कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. जिससे मौत के सटीक कारणों और किसी अन्य तरह की दरिंदगी की पुष्टि हो सकेगी. पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है. वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं.

पुलिस का आश्वासन: जल्द होगा खुलासा

सिटी डीएसपी डॉ.गौरव कुमार ने बताया कि मामले के उद्भेदन के लिए विशेष टीम गठित की गई है. पुलिस ने जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इस घटना के बाद से बेगमपुर इलाके के लोगों में भारी आक्रोश है. स्थानीय लोग बच्ची के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं.